The House reassembled after lunch at thirty one minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are on Private Members' Resolution. Shri Vishambhar Prasad Nishad to continue his speech. Yes, Vishambhar Prasadji, you can continue.

Need for taking welfare measures for farmers in Bundelkhand region and steps for overall development of region - *Contd.*

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः उपसभापति महोदय, मैंने बुंदेलखंड की समस्याओं के बारे में अपना संकल्प रखा था, उस पर मैं अपनी चर्चा जारी रखता हूँ। बुंदेलखंड की हालत बहुत खराब है, वहां हर तीन साल में एक बार सूखा पड़ जाता है और बरसात में नदियों में बाढ़ के कारण सैंकड़ों गांव तबाह हो जाते हैं। भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, जिससे वहां के निवासियों के पीने के पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके। मैं यह संकल्प इसलिए लाया था कि भारत सरकार एक नीति बनाए, कानून बनाए और बुंदेलखंड के लिए अलग से कम से कम एक लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम करे। बुंदेलखंड की हालत इतनी पतली है कि वहां के लोग पलायन करते हैं और आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से एक बात रखना चाहते हैं कि जब देश में रिजर्व पुलिस की व्यवस्था है, रिजर्व आर्मी की व्यवस्था है, तो रिजर्व पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है? पीने के पानी की कमी से लोग प्यास से मरते हैं, उसके लिए भी केन्द्र सरकार को रिजर्व वाटर की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, बुंदेलखंड के हालात ऐसे हैं कि -

"पोखर को मैदान बनाया, मरता हुआ किसान बनाया।
शहर बनाए गांव मिटाए, जंगल और पहाड़ हटाए।
जहर मिले दुकानों में, मरना कितना आसान बनाया।
यह कैसा बुंदेलखंड बनाया, कैसा हिंदुस्तान बनाया?"

मान्यवर, बुंदेलखंड की अपनी भौगोलिक स्थिति है, वहां की हालत खराब है, दाने-पानी की मुश्किलों के बीच प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों को टूटने पर मजबूर कर दिया है। पलायन उनकी नीयत बनती जा रही है, बैंक और साहूकार के कर्ज तले दबा किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन बुंदेलखंड को लेकर जो छाती पीटने की तेज आवाजें आ रही हैं, विलाप के सुर सुनाई दे रहे हैं, दरअसल ये उन गिरोहों के हैं, जिन्होंने बुंदेलखंड के अकाल को अपने लिए उद्योग बना लिया है। किसानों की चिंताओं से उनके घर के चूल्हे दहक रहे हैं। तमाम योजनाएं बनती हैं और वे केवल कागजों में रह जाती हैं। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहां सभ्यता और

* Further discussion on Resolution moved by Shri Vishambhar Prasad Nishad on the 17th March, 2017.

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

संस्कृति की विरासत को देखा और समझा जा सकता है। यहां गांवों में छोटी-छोटी चौपालें बैठती हैं। इन चौपालों में कभी आल्हा और ऊदल की वीरता के गीत गाए जाते थे। पर आज पानी बिना सब कुछ सून होता जा रहा है। दूर-दूर तक पानी नहीं है, जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। पानी की कमी के कारण फसलें उग नहीं रही हैं और पानी की कमी से जानवर मर रहे हैं। यह सूखे का मौसम बुंदेलखंड में न जाने कितनी मौतें देने वाला है। जानवर से लेकर इंसान तक झुलसती गर्मी का सामना पानी के बिना नहीं कर सकते हैं। इस समय गर्मी का मौसम चालू हो गया है। मान्यवर, वहाँ temperature 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। पानी न तो जमीन के नीचे है और न ही आसमान में है। बुंदेलखंड में पेयजल की स्थिति बड़ी विकराल है। स्वच्छ पीने योग्य पानी के प्रबंधन में घोर उदासीनता है। सरकार द्वारा पेयजल, स्वच्छ पानी की योजना बनाई जानी चाहिए। बरसात में जिस प्रकार बाढ़ आती है और उसके लिए योजनाएँ चलाई जाती हैं, उसी प्रकार पीने योग्य पानी के लिए तमाम योजनाएँ चलाई जाती हैं, परन्तु योजनाएँ अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती हैं। मान्यवर, हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में बेतवा और केन नदी को जोड़ने का एक प्लान बनाया गया था। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, लेकिन पता नहीं उस पर अभी तक काम क्यों शुरू नहीं हुआ? अगर उसको पूरा कर दिया जाए, नदियों को तालाबों से link कर दिया जाए, नदी की बाढ़ का पानी कुओं में डाला जाए और तालाबों की तलहटी में कुएँ बनाए जाएँ, तो वहाँ की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

मान्यवर, वहाँ फसलें न होने से किसान परेशान हैं। उनके पास आमदनी का कोई और ज़रिया न होने से लोग या तो गाँवों से पलायन कर रहे हैं या फिर सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज ले रहे हैं। कर्ज न चुका पाने के कारण किसान आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं। अगर आप बुंदेलखंड के हालात का जायज़ा लें, तो आप देखेंगे कि वहाँ आए दिन आत्महत्या की खबरें छपती हैं। मान्यवर, पूरे बुंदेलखंड में अभी तक आँकड़ा आया था कि बाँदा में रबी की फसल का करीब 1.70 अरब का बीमा किसानों द्वारा दाँव पर लगाया गया था। वहाँ लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं और इसके लिए अपनी जमीन को बंधक रखने का काम करते हैं। इसमें जिले के 9 बैंकों ने 39,948 किसानों की 51,800 हेक्टेयर भूमि का बीमा किया था। बीमा कम्पनियाँ मनमाने ढंग से सर्वे कर रही हैं। वहाँ बरसात के पानी से अलसी की फसल होती है, लेकिन बीमा कम्पनियों के द्वारा अलसी की फसल बीमा से मुक्त कर दी गई है। आँकड़ों के मुताबिक बुंदेलखंड में 80.53 फीसदी किसान कर्जदार हैं। बाँदा में कुल बीमा राशि 1 अरब 70 करोड़ 90 लाख 62 हजार रुपए है, जिसका premium 6 करोड़ 96 लाख 35 हजार 268 रुपए है। अगर इन बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों की खेती का क्रेडिट कर्ज में देखा जाए, तो 6 अरब रुपए की फसल किसानों ने कर्ज से पैदा की है, जिसे 90 फीसदी मौत के मौसम ने बरबाद कर दिया है।

मान्यवर, अगर किसान को आत्महत्या से बचाना है, तो उसकी जमीन, मवेशी और चारे को बचाना होगा। अगर उसे सक्षम बनाना है, तो पहले उस तक बीज, खाद और तकनीक को वाजिब दाम में पहुँचाना होगा। भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, बाजार की समझ पैदा करनी होगी। आँकड़े

बताते हैं कि फल और सब्जियों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन होने के बावजूद भारत कुपोषित है। यहाँ कुल उत्पादन की 40 फीसदी सब्जियाँ और फल उपभोक्ताओं के पास पहुँचने से पहले ही सड़ जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। मान्यवर, यह स्थिति है। हमें ऐसा देखने को मिलता है, बड़ी विडंबना है। पानी की बरबादी रोकने के लिए, लोगों के पलायन को रोकने के लिए, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कोई तकनीक या उस तरह की फसलों का इंतजाम किया जाना चाहिए, जिससे बरसात के पानी में वहाँ की फसलें उगाई जा सकें। मान्यवर, मध्य प्रदेश के सागर संभाग के ओरछा तथा दतिया और उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के सभी जिले बुंदेलखंड भूभाग में हैं। बुंदेलखंड की विडम्बना है कि यह एक सामाजिक एवं भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंटा हुआ है। लगभग 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इस इलाके की आबादी 3 करोड़ से अधिक है। यहां हीरे और ग्रेनाइट की बेहतरनी खदानें हैं। इस क्षेत्र के जंगल आंवला और तेन्दू पत्ते से अटे पड़े हैं, लेकिन इनका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता है।

महोदय, दिल्ली, लखनऊ और पंजाब तक जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनमें वहां के अधिकांश लोग गारा, गुम्मा, गिट्टी और ईंट का काम करते हैं। इसके कारण बुंदेलखंड से लोग इन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को करने हेतु पलायन करते हैं। पोषण, पलायन और भुखमरी को तो वे अपनी नियति समझते हैं, जबकि खनिजों और अन्य सामानों से बुंदेलखंड, दोनों राज्यों की सरकारों को आवश्यकता से अधिक आमदनी देता है, लेकिन इन सरकारों द्वारा उस इलाके के विकास पर 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है।

महोदय, बुंदेलखंड के पन्ना में हीरे की खदानें हैं। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला ग्रेनाइट दुनिया में धूम मचा रहा है। यहां की खदानों में गोरा पत्थर, सीमेंट का पत्थर, रेत और बजरी के भंडार हैं। इलाके के गांव-गांव में तालाब हैं, जहां की मछलियां कोलकाता के बाजार में आवाज़ लगाकर बिकती हैं। इस क्षेत्र के जंगलों में मिलने वाले तेंदू पत्ते को green gold कहा जाता है। आंवला और हर्र जैसे उत्पादों से जंगल लदे हुए हैं। वहां के आदमियों की मेहनत के साक्षी खजुराहो, झांसी और ओरछा जैसे पर्यटक स्थल हैं, जहां पूरे विश्व के लोग भ्रमण करने आते हैं। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से कुल मिलाकर दोनों राज्यों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल जीरो है। बुंदेलखंड के सभी कस्बों और शहरों की बसावट एक ही पैटर्न पर है। चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों की तलहटी में दर्जनों छोटी-छोटी ताल-तलैया हैं और उनके किनारों पर बस्ती है। टीकमगढ़ जैसे जिले में भी अभी तीन दशक पहले तक एक हजार से ज्यादा तालाब थे। पक्के, हरियाली से घिरे विशाल तालाब बुंदेलखंड के हर गांव और कस्बे की सांस्कृतिक पहचान हुआ करते हैं।

मान्यवर, आजादी में भी हमारे बुंदेलखंड का इतिहास रहा है। आजादी की लड़ाई में वहां के लोगों ने अपना योगदान दिया है। हमने बुंदेलखंड की सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को सदन में एक प्रश्न पूछा था कि 'प्रधान मंत्री सिंचाई योजना' के अंतर्गत बुंदेलखंड के चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, जालौन सहित दोनों राज्यों के किन-किन क्षेत्रों के खेतों को सिंचित करने की व्यवस्था है? सरकार ने कहा कि अभी स्कीम मंजूर की जानी है। अभी

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

तक इनकी स्कीमें कागजों पर ही चल रही है। अभी वे धरातल पर ही नहीं उतरी हैं। जिस तरह से इन्होंने सपना दिखाया, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया गया। अब इनकी दोनों जगह सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केन्द्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। वैसे तो नया राज्य बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अलग राज्य बनाने से पहले वहां की स्थिति को देखिए और वहां की जो परेशानियां हैं, जो वहां भुखमरी है, उसका हल ढूंढ़िए। वहां जितने भी तालाब हैं, उन पर अतिक्रमण किया जा चुका है। इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, लेकिन बार-बार आदेश होने के बावजूद जितने भी पुराने तालाब थे, उन सभी पर अतिक्रमण किया जा चुका है और उन्हें पाटकर आबादी बनाई जा रही है। इसके कारण आज बुंदेलखंड के लोग तमाम सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं।

मान्यवर, बुंदेलखंड की समस्या को लेकर सरकार हर साल पैकेज के नाम से करोड़ों रुपए अवमुक्त कर रही है, पर उस धनराशि को उपयोग में न लाकर समस्या को बरकरार रखा जा रहा है। यदि केन्द्र से मिलने वाली इस धनराशि को पूर्णरूप से व्यय कर दिया गया होता, तो वहां आज किसान जिन हालात से गुजर रहे हैं, वैसी स्थिति पैदा नहीं होती। यदि आप पिछले छः साल के पैकेज के आंकड़ों को देखें, तो तस्वीर साफ हो जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि समूचे बुंदेलखंड में किसानों की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और वहां के अधिकारी हैं। वे जिस तरह से estimate बनाते हैं... पिछला पैकेज गया, उन लोगों ने तमाम चेक डैम्स बनाए, लेकिन ऐसी जगह चेक डैम बनाए, जहां पर पानी नहीं रुकता है। ऐसे ही किसानों के खेत में तालाब बना, लोगों से कहा कि आप तालाब बनाइए, लेकिन ऐसी जगह तालाब बना दिए, जहां पर पानी पहुंच ही नहीं सकता है। इस पर करोड़ों रुपए बरबाद हो गए।

मान्यवर, हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में खास तौर से पाठा क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। यह सबको पता है कि गर्मी आते ही बुंदेलखंड में पानी की समस्या देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। वहां पर पानी का जो टैंकर आता है, वह मुश्किल से आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाता है यानी एक टैंकर पानी तुरंत उड़ जाता है। वहां पर पानी की लूट होती है। उसमें भी जो असरदार लोग हैं, वे लोग पानी के पूरे के पूरे टैंकर को लूट कर अपने-अपने घरों में पहले ले जाते हैं और जो गरीब आदमी है, जो लड़-झगड़ नहीं सकता है, वह एक लीटर पानी के लिए भी तरसता रहता है। उसको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। पता चलता है कि उसको पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, जल विभाग का कहना है कि जब बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तब हम पानी कहां से लाएं? चूंकि जो जल निगम है, जल संस्थान है, ये पानी का इंतजाम करते हैं, लेकिन ये अपना बहाना बता देते हैं कि हमारा tubewell खराब है। बिजली वाले कहते हैं कि उसकी यांत्रिक मोटर खराब है और यांत्रिक वाले कह देते हैं कि बिजली सप्लाई नहीं आ रही है। इस तरह से तमाम जो tubewells लगाए भी जाते हैं, जिनमें पानी की सप्लाई होती है, चाहे वे सिंचाई के लिए हों या पीने के पानी के लिए हों, वे सही ढंग से नहीं चल पाते हैं।

मान्यवर, मानिकपुर क्षेत्र से लेकर पूरे इलाके में, जिसको पाठा क्षेत्र कहा जाता है, आज वहां 4-4, 5-5 किलोमीटर तक कहीं पानी नहीं है। अभी हमने कहा था कि जैसे हमारे पास रिजर्व पुलिस की व्यवस्था है, रिजर्व आर्मी की व्यवस्था है, उसी तरह से केन्द्र सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए, आज़ादी के 70 साल बीत गए, रिजर्व वाटर की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हर आदमी के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। वैसे तो सबको मकान, सबको शिक्षित करने का काम, सबको चिकित्सा देने का काम केन्द्र सरकार को करना चाहिए था, लेकिन चुनाव के गणित में देखने को मिलता है कि जहां इनकी सरकार होती है, वहां तो अतिरिक्त मदद मिल जाती है और जहां इनकी सरकार नहीं होती है, वहां उतनी भी नहीं मिल पाती है, जितनी मांग की जाती है। पिछली बार हमारी प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सूखे से निपटने के लिए पैसा मांगा और बुंदेलखंड पैकेज में जो शेष पैसा पड़ा था, वह मांगा था, लेकिन समय से पैसा नहीं मिला, इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों को समय से जो राहत मिलनी चाहिए, जो अनुदान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया।

मान्यवर, जिस तरह से केन्द्र सरकार 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत रकम निर्धारित की है, वह बहुत कम है। आप इसके लिए एक लाख रुपए देते हैं, आज महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि एक लाख में एक छोटा सा मकान दस बाय दस का नहीं बन पाता है। सीमेंट, लोहा, बालू और लेबर इतना महंगा है, इसलिए इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 'डा. राम मनोहर लोहिया आवास योजना' के तहत 3 लाख 5 हजार रुपए दिए जाते हैं, उसी तरह हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जो भी पात्र लोग हैं, बीपीएल धारक लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं, उनको मकान देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, बुंदेलखंड पैकेज के तहत लघु सिंचाई विभाग को रिचार्ज, डीपनिंग/रिनोवेशन ऑफ डग वेल के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए आबंटित किए जाते हैं। इस योजना के तहत सूखे कुओं को ब्लास्टिंग कर उनको गहरा करके पानी उपलब्ध कराने का काम होता है, लेकिन देखने को मिलता है कि वह काम पूरा नहीं हो पाता है। उसमें बारिश के पानी से रिचार्ज करने की भी योजना शामिल है ताकि बारिश के पानी को बरबाद न होने दिया जाए, बल्कि उसे धरती के सीने में पहुंचाया जाए। मान्यवर, वैसे तो 2010 से 2015-16 तक तमाम योजनाएं बनीं और उनके लिए पैसा भी दिया गया, लेकिन 6 सालों में जारी की गई धनराशि के बारे में देखें, 2010 से लेकर 2016 तक, जो कुल 25,965.23 लाख रुपए आबंटित किए गए, उसकी तुलना में 4301 लाख रुपए ही वहां उपलब्ध हो पाए। जिस तरह की वहां अवस्थाएं हैं, उन्हें ठीक करने के लिए ही मैंने यह संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है। हमारे यहां जानवरों से भारी दिक्कत है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां नीलगायें और देसी गायें दोनों भारी संख्या में है। मैं आपके माध्यम से बुंदेलखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो गाय पालते हैं, जब तक गाय दूध देती है, तब तक आप उसे रखते हैं, उसका बछड़ा बांधकर रखते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो आप उसे छेड़ देते हैं। इस मामले में क्षेत्रवासी भी बराबर के दोषी हैं। अगर कोई गाय पालता है तो गाय के चारे, भूसे और पानी का इंतजाम भी करना चाहिए, अन्यथा गाय मत पालिए। देखने में आता है कि हजारों देसी गायें वहां ऐसे ही घूमती रहती हैं, जो अपने मालिक किसान का ही खेत चर जाती हैं। किसान क्या करता है - अपने खेत की रखवाली करता है। जैसे ही

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

गायें आईं, उन्हें एक खेत से दूसरे खेत में धकेल दिया जाता है। कुछ लोग गांवों में रखवाली करते हैं। वे लोग भी अपने गांव से गायों को दूसरे गांव छोड़ आते हैं। जब दूसरे गांव वालों को पता चलता है, तो वे इनके गांव में छोड़ जाते हैं। इस तरह गायें एक दूसरे की फसलों का नुकसान करती रहती हैं। हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे प्रत्येक न्याय-पंचायत में एक गौशाला या पशु आश्रय केन्द्र बन सके। उसमें ग्राम पंचायतों का contribution भी रहे और केन्द्र तथा राज्य सरकारों का भी रहे, जिससे रखवाली करने का काम, गौशाला में अंशदान करने का काम हो सके। यदि किसी के पास भूसा ज्यादा है तो वह गौशाला को दान में दे दे। यदि ग्राम पंचायत में गौशाला बन जाए तो किसानों की फसल भी बरबाद होने से बचेगी और देश की उपज भी बढ़ेगी जिससे हमारा देश खाद्यान्न में खुशहाल बन सकता है।

महोदय, हमारे यहां कुटीर उद्योग-धंधों की भारी कमी है। बुंदेलखंड के लिए सरकार को विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज बुंदेलखंड से किसान पलायन कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार इसका सर्वे कराए। जब तक हम सर्वे नहीं कराएंगे, हमें उनकी basic problems पता नहीं चल पाएंगी। किसान के पास खेत तो हैं, लेकिन सिंचाई के साधन न होने के कारण उत्पादन नहीं होता, जिससे वह कर्जदार हो जाता है। वहां के बैंक और साहूकार दोनों मिलकर किसानों का शोषण करते हैं। कोई बैंक बिना पैसा लिए, बिना दलाली लिए किसान का Credit Card तक नहीं बनाता। यदि Credit Card बन गया तो उसका renewal करने में भी पैसा ले लेता है। वहां चूंकि भोले-भाले गरीब लोग हैं, मैं यहां बुंदेलखंड के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि गांव में जितने दलाल हैं, जो बैंकों में बैठते हैं, सरकार को चाहिए कि वह सभी बैंकों को दलाल-मुक्त बनाए। हर बैंक में CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन लोग हैं, जो बार-बार वहां आते हैं और मैनेजर के पास बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही जितनी केन्द्र की योजनाएं हैं, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। ...(**समय की घंटी**)...

आपने कानून बनाया है कि मनरेगा में जो घपला करेगा, गड़बड़ी करेगा, हम उसे जेल भेजने का काम करेंगे। मनरेगा में अभी 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था है। वहां की पंचायत मिलकर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप सुनिए। आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं। पिछले दिन भी आपने कहा था। अब conclude कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः मेरी मांग है कि जिस उद्देश्य से मैं यह संकल्प सदन में लाया हूं, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The total time for this is two hours. If you alone speak, then, there will be no supporters for you. You leave some time for your supporters also.

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरी मांग है कि बुंदेलखंड में जो मनरेगा योजना चल रही है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, उन्हें 100 दिन के स्थान पर 300 दिन के काम की व्यवस्था सरकार करे, जिससे लोगों का पलायन रुक सके। मेरी मांग है कि 24 घंटे वहां बिजली मिले और लोगों को केन्द्र की विशेष योजनाओं का लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। आप वृद्ध लोगों को 300 रुपए पेंशन के रूप में देते हैं। अनेकों वृद्धाएं वहां खड़ी हो जाती हैं। मेरी मांग है कि उस राशि को बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपए किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Please sit down.

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः मान्यवर, आपकी जो 300 रुपए की पेंशन योजना है, हम देखते हैं कि गाँवों में वृद्धाएँ उस 300 रुपए के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं, इसलिए उसको कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह कर दें। ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, मैंने यह संकल्प इसलिए प्रस्तुत क्या है कि वहां के लोगों का पलायन रुक सके, वहाँ आत्महत्याएँ रुक सकें। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः निषाद जी, हो गया। अब आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सरकारी विधेयक लाएँ और बुंदेलखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम करें, जिससे वहाँ की गरीबी, पलायन और आत्महत्याएँ रोकी जा सकें। ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all, Mr. Nishad. Thank you. Now, Shri Ananda Bhaskar Rapolu. You take maximum ten minutes.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): I will take fifteen minutes. Sir, you are putting restrictions even on this!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are three other speakers.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, you are much more liberal today, because today is March 31st.

Respected Deputy Chairman, Sir, जब बुंदेलखंड याद आता है, तो हमें इतिहास के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी द्वारा मैया जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ मिलकर बनाई गई उनकी कर्मभूमि चित्रकूट की याद आती है। जब बुंदेलखंड की याद आती है, तब राजा विक्रमादित्य याद आते हैं, राजा छत्रसाल याद आते हैं, झांसी की रानी याद आती हैं और मस्तानी वाले पेशवा बाजीराव भी याद आते हैं। उस इतिहास की बात याद आने के बाद और आज, मेरे भाई विशम्भर प्रसाद निषाद जी का भाषण देहादि-ध्वनि से सुनने के बाद बुंदेलखंड के हालात के बारे में हमें बहुत दुःख हो रहा है। अयोध्या से पवन पावन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सरयू पार होने के लिए उस ऐतिहासिक मौके पर एक निषाद भाई का सहारा लिया था। रामचन्द्र जी का चित्रकूट होने के बावजूद वह इतना

[Shri Ananda Bhaskar Rapolu]

3.00 P.M.

दुःख में है कि हम सोच भी नहीं सकते। यह चैत्र नवरात्र है और विक्रम सम्वत् के तहत नववर्ष शुरू हुआ है। 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और 14 जिलों वाले बुंदेलखंड का विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में है। बुंदेलखंड के आज का जो दुःख है, वह पूरे भारतवर्ष और भारत सरकार को अपनी ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को महसूस कराता है।

I am interested in Bundelkhand as I belong to Telangana. When we were struggling to attain Statehood to our Telangana from the then united State of Andhra Pradesh, we used to understand and connect with the ground realities of Marathwada and Bundelkhand.

My leader, Vice-President of Congress Party, Shri Rahul Gandhi, travelled extensively into the interiors of Bundelkhand and made out a programme to address the complications of Bundelkhand to contain the distress of the people there. But, as per the latest reports, in India, if we have to understand the rural distress, the dire picture is available only of Bundelkhand. हम गाय के लिए तरस रहे हैं, मगर बुंदेलखंड के कृषक भाई नीलगायों की वजह से दुःख से घिरे हैं।

There is a problem of widespread destruction of the agricultural fields by *neel gais*. The State Governments of both the States, now and then, ensure certain programmes, but they are not creating any clusters to contain the destruction of fields by checking the movement of *neel gais.* Until and unless you have a feeder programme, until and unless you provide water for the *neel gais* and other livestock population, they will simply move into the villages.

Bundelkhand is not only a mountainous region, as mentioned by Nishadji, it is also having a lot of mineral resources. It is having the agricultural originality. Even after that, why are we not able to alleviate the complications and distress of the farming community and the migrating community of Bundelkhand? We need to have case-by-case study of all the districts. The ethnobotanical studies are revealing plants' complications. The *neel gai* complication has been highlighted not only through the national media, but also international media. Even after having the great heritage and the very hardworking people, those who are known for day-in-day-out manual labour, they are not able to feed their stomach. That is why the prevalence of suicides and burning of fields and killing of *neel gai* and other cattle are throwing a human challenge to the advanced human civilization, that is, India. The Indian Government, while taking the ground realities and reports from the State Governments of Uttar Pradesh and

Madhya Pradesh, shall come out with a detailed proposal for the comprehensive development of the people and their livelihood standards. If we assess through the Human Development Index or even if we assess through the Human Poverty Index, the region of Bundelkhand will throw a very pathetic picture. Their health conditions, their educational standards are not at all improving. These parameters are before you. Why are you not able to evolve a programme? आपके पास सिर्फ नारा है, आपके पास कार्यक्रम नहीं है। मध्य प्रदेश का संकट, बुंदेलखंड के, मध्य प्रदेश के प्रांतों का संकट यहां बैठे वरिष्ठ नेता, माननीय मंत्री श्री थावर चन्द गहलोत जी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। Why are we not able to pinpoint the problem and find a solution? When we are having a scope to make water available from the Narmada and the Yamuna rivers, why are we not able to evolve an irrigation programme in order to ensure a perennial water source? Why have we not identified sanctuaries to contain the spreading of *neel gais?* Why are we not having any programme to deal with the severe drought? As I enquired from both the States, the State of Madhya Pradesh and the State of Uttar Pradesh, there is no fodder support programme to cater to the needs of the Bundelkhand region. Though we, the people of Telangana, were having great catchment areas of the Krishna and Godavari, yet we had continuously faced the problem of irrigation because of similar reasons. But that is a different saga of deprivation and denial. Wherein, here, we need to have a programme and also maximum financial support to evolve, so that there is a perennial water source, with which they can move forward. Today, even for a glass of water, Bundelkhand rural areas are struggling. They are not going to have any relief because there is no immediate support programme from both the Governments. This is time for the Union Government to focus on this and come out with a comprehensive programme. Summers will come and go; droughts are coming and going; and, people like Nishadbhai are taking up and raising their issues before the House; but, they are just going into the records of the Indian Government and the Indian Parliament. Today, though the people in Bundelkhand are having the festive season of Chaitra Navratri, they are not in a position to celebrate their festival. They are not in a position to celebrate the forthcoming festival, Sri Rama Navami, which is the event to conclude the Chaitra Navratri. But, by that time, at least, if you are seriously concerned with the Chitrakoot, its heritage and history, please look into it and try to alleviate the worries, complications and the problems of Bundelkhand. This is the specific urge. The proposal initiated by Shri Vishambhar Prasad Nishad is genuine and it must be supported with a proper mechanism so that the relief and support goes to every nook and corner of Bundelkhand. Thank you.

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): उपसभापति जी, आदरणीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने बुंदेलखंड, जो सात-आठ साल से एक प्रकार से अकाल की स्थिति में है, वहां की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के सामने तुरंत उनकी कुछ समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से कई मांगें रखी हैं। नीलगाय के कारण कई समस्याएं हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं होने के कारण गायों का रास्ते पर छोड़ दिया जाता है, खुद के खाने के लिए नहीं है इसलिए सब बुंदेलखंड से पलायन करके, बुंदेलखंड खाली करके, लाखों लोग बाहर जाकर जी रहे हैं। इस प्रकार की एक विशिष्ट परिस्थिति के अंदर अपनी मनोवेदना को आदरणीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से हाउस के अंदर प्रस्तुत किया है। मैं उनकी वेदना को समझता हूं और सरकार भी इसके बारे में गंभीरता से सोचे, यह मेरी विनती है।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर माननीय उपसभापति के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज हम इस बुंदेलखंड की चर्चा कर रहे हैं। कभी हम मराठवाड़ा की चर्चा उधर से सुनते हैं, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, हम अकाल की दयनीय स्थिति मराठवाड़ा में देखते हैं, तो दिल दहल उठता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने अपने तेलंगाना के बारे में कहा कि किस प्रकार की दयनीय स्थिति में तेलंगाना को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा है। कुछ साल पहले इसी सदन के अंदर 371 (जे) के नाम से एक बिल पास किया गया, जो हैदराबाद-कर्णाटक कहा जाता है, आज वहां के लोग उसे कल्याण कर्णाटक नाम से कहते हैं। आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस ने भी उस दिन कन्नड़ में बात करते हुए, उस प्रदेश के 371 (जे) के बारे में समर्थन किया था। कानून बनते हैं, लेकिन वहां जारी नहीं होते हैं। जो कानून वहां पर 371(जे) के तहत बना है, आज तक एक बार भी वहां के elected representative की मीटिंग नहीं हुई, जबकि कानून में यह लिखा हुआ है कि साल में एक बार मीटिंग बुलानी चाहिए, वैसा ही विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने कहा है। कई बार सरकार का बजट आता है, बांध बनते हैं, लेकिन सैंकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ऐसी जगह पर बांध बनते हैं, जहां पर एक बूंद पानी भी नहीं रुकता है। तो कहीं-न-कहीं गड़बड़ हो रही है। देश की अनमोल संपत्ति ओडिशा में है, झारखंड में है, लेकिन वहां के लोग अपने हाथ आंसुओं से धोते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कहीं-न-कहीं हमारी सोच व कार्य-प्रणाली में गड़बड़ है। विशेषकर यूरोप और अमेरिका से भौतिक सुख का एक कल्चर हमारे देश में आ गया है, उस के कारण हम अपने अंदर की ताकत को भूल गए हैं और केवल बाहरी सुविधा की बात करते हैं। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधा किसी को देने से वह इंसान बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। जब तक उसकी आंतरिक शक्ति को जाग्रत नहीं किया जाता है, उस के अंदर emotional quotient नहीं भरा जाता है, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता है। सर, उस प्रदेश के लिए आदरणीय विशम्भर प्रसाद जी ने 1 लाख करोड़ की मांग रखी है, मैं कहूंगा कि 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ देने के बाद भी बुंदेलखंड का वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। फिर उस के लिए हमें क्या करना होगा? बुंदेलखंड की स्थिति ऐसी है कि उस के 7 जिले मध्य प्रदेश् के अंदर और 7 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उनकी संस्कृति को तोड़ दिया गया है और बार-बार politically जिले बदले जाते हैं, जनपद बदले जाते हैं, जिस कारण उन्हें कोई ठोस मालिक समझ नहीं आता है। बच्चे कभी एक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और कभी दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनते हैं। इस तरह आज

बुंदेलखंड एक दयनीय स्थिति में खड़ा है। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि वह उनकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए तुरंत सहायता दे, वहां के किसानों की समस्या के लिए, वहां की गौ संपत्ति की समस्या के लिए सहायता दे। वहां एक जमाने में 400 तालाब थे, वे कहां गए? वहां बहुत हरियाली थी, वह कहां गयी? वहां हीरे-पन्ना थे। पन्ना जिस नाम से जाना जाता है, आज क्यों ऐसी दयनीय स्थिति वहां हो गयी है? जिस धरती का नाम लेकर छत्रसाल महाराज का हम नाम लेते हैं, वैसी धरती में हम रानी झांसी का नाम लेते हैं, मैथिलीशरण गुप्त जैसे श्रेष्ठ कवि वहां हुए, बनवारी लाल जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार व कवि वहां पैदा हुए, ऐसे महान पुरुषों की आंसू बहा रही धरती के बारे में बात करने के लिए हम आज यहां खड़े हैं। इसलिए कहीं-न-कहीं हमारी सोच में गड़बड़ है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वह तुरंत वहां की कनिष्ठतम भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ-न-कुछ सुविधा दे, परंतु वस्तु की गहराई में जाना भी जरूरी है। यह तेलंगाना की समस्या हो सकती है, मराठवाडा की समस्या हो सकती है, कल्याण कर्णाटक की समस्या हो सकती है, बुंदेलखंड की समस्या हो सकती है और बहुत बड़ी खनिज संपदा से भरपूर झारखंड और ओडिशा की समस्या हो सकती है। इन के पास इतना सब होते हुए भी आज ये आंसू क्यों बहाते हैं? इसलिए वहां की जनता की आत्मा को जगाने के काम किए बिना बाहर से कितनी भी सुविधा दी जाएगी, उस से इंसान निकम्मा बनेगा, वहां के लोग नकली बांध बनाएंगे और करोड़ों रुपया ऐसे ही पानी में बह जाएगा। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री से एक विनती करूंगा कि आप लोग अपने मंत्रालय द्वारा पूरे बुंदेलखंड का सर्वे कराएं। इतना ही नहीं, जितने भी ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का नाम आता है, वहां पर एक बार टोटल सर्वे कराएं कि वहां का सांस्कृतिक महत्व क्या है, वहां का ऐतिहासिक महत्व क्या है, वहां के जन-जीवन की विशेषता क्या है? जब तक इस तरह से गहराई में नहीं जाएंगे और केवल ऊपर से पॉलिश करेंगे तो समस्या का निदान नहीं होगा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इस तरह वहां के मनोविज्ञान को समझकर लोगों के जन-जीवन में एक नयी जान लाने की दृष्टि से सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सर, मैं रोज सदन में केवल भौतिक सुख की चर्चा ही सुनता हूं। दुनिया के अंदर, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ऐसे देश हैं, जहां इंसानियत अच्छी है। लोग मेहनत करके जीते हैं, दुनिया में ह्यूमन क्वालिटी में नम्बर one, two पर आते हैं। हमारे यहां रोज भौतिक मांग करते हैं, लेकिन रोज हम पशुता की तरफ चले जा रहे हैं। क्या हम अपने आपको इंसान कहलाने लायक नहीं हैं? मैं कृषि मंत्री जी से इस नाते से यह आग्रह करूंगा कि जब वे जवाब दें, तो बताएं कि अगर आप बुंदेलखंड की समस्या का सच्चा निराकरण करना चाहते हैं, तो उसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वहां का पौराणिक इतिहास और वहां की धरती, वहां की जो तीन प्रकार की मिट्टी है, उस मिट्टी का चिंतन - और वहां के 400 तालाब कहां गए? आज ऐसी दयनीय स्थिति क्यों आई, किन विकृतियों के कारण यह विकृति आई है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? भारत सरकार एक दूरदृष्टि की योजना बनाकर केवल बुंदेलखंड ही नहीं, बुंदेलखंड को आधार बनाकर पूरे भारत में इस प्रकार सदन में रोज आंसू बहाने की बात सुनते हैं, तो इसका कहीं-न-कहीं निदान करना होगा। जब कभी महाराष्ट्र की बात आएगी, तो मराठवाड़ा के लोग खड़े हो जाएंगे, जब तेलंगाना की बात आएगी, तो वहां के लोग खड़े हो जाते हैं, जब हैदराबाद और कर्णाटक की बात आएगी, तब हम खड़े हो जाते हैं। काफी बड़ी सम्पदा रख कर ओडिशा, झारखंड के लोग आंसू बहाते हैं, वहां भी ऐतिहासिक

[श्री बसावाराज पाटिल]

महापुरुष हुए हैं। वहां की धरती में भी अनमोल ताकत है। वहां भी असाधारण व्यक्ति रहे हैं। उनकी आत्मा को जगाएंगे, उनके पुरुषार्थ को जगाएंगे, तो उनकी कर्मठता बढ़ेगी। उसके कारण कल जो भी पैसा आएगा, उसका सदुपयोग होगा और जनता के हित में खर्च होगा तथा लोग परिश्रमी बनेंगे। इसके कारण वहां के जनजीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए मैं विशम्भर प्रसाद निषाद जी के इस संकल्प का समर्थन करता हूं, परन्तु इस भौतिक समर्थन से ...(**समय की घंटी**)... सुविधा से सामने होता है। मैं आदरणीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि सदन में जो प्रदेश बार-बार चर्चा में आते हैं, इनके बारे में वे गहराई से अध्ययन करें, उसकी रिपोर्ट लिखें और संबंधित राज्य सरकारों से बात करें। इस सदन में बार-बार आंसू बहाकर, अपने दुख को प्रकट करने की स्थिति न हो, अगर सरकार ऐसी कोई ठोस योजना बनाकर काम करेगी, तो समस्या को लम्बे समय तक सुलझाने का मौका मिलेगा। ...(**समय की घंटी**)... ऐसा श्रेष्ठ काम करें, इसलिए मैं विशम्भर प्रसाद निषाद जी की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं कि केवल इन मांगों से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं आप से विनती करता हूं कि इन मांगों के साथ आप सरकार से विनती कीजिए कि वहां का पूरा अध्ययन करके स्थायी समस्या के हल के लिए कोई ठोस काम करे। अभी तुरंत किसी चीज की जरूरत है, तो वहां की राज्य सरकारों से बात करके, वहां की जनता से बात करना जरूरी है। इस प्रकार से समस्या का हल नहीं होगा, इतना कहते हुए मैं एक बार फिर सरकार से विनती करता हूं कि एक अनन्त काल का सॉल्यूशन निकालने की दृष्टि से प्रयास करें, धन्यवाद।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): उपसभापति महोदय, आज श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी बुंदेलखंड की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और किसान की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए जो संकल्प लाए हैं, मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने वहां के किसानों, नौजवानों और महिलाओं के बारे में बताया है। आज वहां कितने किसानों ने आत्महत्या की है और कितने नौजवान वहां पलायन हुए हैं, इस पर भी इन्होंने विस्तारपूर्वक अपने वक्तव्य में बताया है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड, जो ऐतिहासिक रहा है, जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, जब हम बचपन में थे और रामायण का पाठ वगैरह होता था, तो चित्रकूट के लिए कहा जाता था कि,

"चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीर,
तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर।"

आज उस बुंदेलखंड की क्या स्थिति है, इसकी ओर देखने की जरूरत है। जैसा अभी हमारे आनंद भास्कर रापोलू जी बोले हैं, हमारे पाटिल साहब बोले हैं, उस हिसाब से परिस्थिति, खास कर पानी की परिस्थिति बहुत ही खराब है, जबकि उस क्षेत्र में पंचनद मौजूद हैं। वहाँ पाँच नदियाँ बहती हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से केन नदी बहती है। उस नदी को बरबाद करने वाले लोग कौन हैं? जहाँ पाँच नदियाँ बहती हों, आज वहाँ के लोग पानी के लिए त्राहिमाम् हैं। जहाँ पाँच नदियों का समागम हो, जहाँ पाँच नदियाँ बहती हों, वहाँ का किसान पानी पाने के लिए मजबूर हो, यह कैसी परिस्थिति है? मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि इसका कोई सर्वेक्षण कराया गया है या नहीं?

वहाँ पर बालू माफिया है, जिसने वहाँ से बालू छान-छानकर, बालू निकाल-निकाल कर उन नदियों को बरबाद कर दिया है। जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं, इन नदियों को यह बालू माफिया बरबादी की ओर ले गया है, जिसके कारण आज किसान पानी के लिए बरबाद हो रहे हैं। वहाँ पर किसान के साथ-साथ आम नागरिक भी बरबाद हो रहे हैं। अगर जीने के लिए किसी चीज़ को आवश्यकता में गिना जाता है, तो पानी को गिना जाता है। आप इस पानी को वहाँ पर बना सकते हैं, आप पानी को एक तरह से ऐसे बना सकते हैं कि आने वाले समय में इन पाँच नदियों को और दुरुस्त कर दिया जाए, उन पर खर्च कर दिया जाए। आप ऐसा करेंगे तो लोग वहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नौजवान पलायन नहीं करेगा, कोई भुखमरी नहीं होगी और हमारे किसान भी आत्महत्या नहीं करेंगे। आपको इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पर, मूल रूप से जो बालू माफिया है, उस बालू माफिया के कारण पूरी नदी बरबाद हुई है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की आजकल एक घोषणा है। वे बहुत जोर-शोर से बोल रहे हैं कि हम खैरात नहीं देंगे, खैरात देना, यानी गुलाम बनाना। हम रोजगार देंगे, अवसर देंगे, हम अवसर के लिए रोजगार देंगे। आपके सामने बुंदेलखंड सबसे बड़ा उदाहरण है आप चाहें, तो उसे रोजगार से जोड़कर यह कर सकते हैं। प्रधान मंत्री जी की यह जो घोषणा है कि हम अवसर देंगे, उस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहूंगा कि आज बुंदेलखंड के नौजवानों को, किसानों को उस अवसर की जरूरत है।

आज, अभी हमारे विशम्भर प्रसार निषाद जी बोल रहे थे कि आप वहाँ पर घर बनाने के लिए पैसा देते हैं, इंदिरा आवास में जो पैसा देते हैं, मैंने कई बार इस संबंध में, सड़क पर और संसद में भी बोला है कि आप जो घर बनाकर देते हैं - हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि हमें इंदिरा आवास दिला दीजिए, किसी को इंदिरा आवास दिला दीजिए, आज उसका बेटा भी हमारे पास आ रहा है कि हमें इंदिरा आवास दिला दीजिए। देश ने कहाँ विकास किया है? देश के किसान, गरीब आदमी ने कहाँ विकास किया है? आज घर बनाने के लिए उसे इंदिरा आवास पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मैं प्रधान मंत्री की सोच के लिए उनको दाद देता हूं कि उन्होंने सोचा है कि मैं अवसर दूंगा, खैरात नहीं दूंगा। खैरात देने की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि आज बुंदेलखंड को खैरात चाहिए भी नहीं, वहाँ के लोगों को अवसर चाहिए। आप पानी के लिए वह अवसर दीजिए, आप किसान को वह अवसर दीजिए। आप उनको अवसर दीजिए और ऐसा अवसर दीजिए कि आने वाले दिनों में वहाँ का किसान बुलंद हो और अन्न उपजाकर देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करे। बुंदेलखंड के लोगों को यह अवसर चाहिए। मुझे वह बात याद आती है, जब उसका बाप मेरे पास आता था कि हमें इंदिरा आवास दिलवा दीजिए, लेकिन आज 20, 25 या 40 बरस के बाद उसका बेटा भी उसी राह पर खड़ा है कि हमें इंदिरा आवास ही चाहिए, इसका मतलब है कि स्थिति वही है। हमें खैरात नहीं चाहिए, इसलिए आप सिर्फ अवसर देने का काम करें। यह अवसर कब मिलेगा? आप इन पाँच नदियों को ठीक कीजिएगा, पाँच नदियों को माफियाओं से बचाइएगा, आने वाले दिनों में आप इन पाँच नदियों को जोड़ने का काम कीजिएगा। वही केन नदी यमुना में आकर मिलती है, जो यमुना नदी दिल्ली तक आती है, तो उस पानी को सिंचित करके किसान को दिया जा सकता है। वहां सबसे बड़ी समस्या पानी की है और फिर दूसरी समस्या नीलगाय की है।

[श्री बसावाराज पाटिल]

महोदय, उस क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी समस्या नीलगाय को लेकर है। किसानों के साथ यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नीलगाय के साथ गाय जोड़ दिया गया है। अगर नीलगाय के साथ गाय न जोड़ा जाता, तो उसको हिन्दू भी मार कर खा जाता, लेकिन गाय का नाम हिंदू की मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे नहीं मारा जाता है। हमारे बिहार में कई जगहों पर नीलगाय को मारने का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, इस माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि आप नीलगाय से किसान को बचाने के लिए कोई नियम बनाइए, जिससे किसान को नीलगाय से बचाया जा सके। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड, एक प्रकार से राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूपे से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं कई बार बुंदेलखंड गया हूँ, बांदा गया हूँ, चित्रकूट गया हूँ, वहां के लोगों को मैंने देखा है, वहां गरीबी बहुत है। उस गरीबी को दूर हटाना है। गरीबी हटाओ, हटाओ, हटाओ बहुत बार नारा लगा, लेकिन गरीबी आज तक हट नहीं सकी। क्या किसी को गरीबी हटाने के लिए अवसर नहीं मिला? गरीब बनाओ, बनाओ, बनाओ, गरीब को कितना गरीब बनाओ, इसी पर राजनीति चलती है और सिर्फ वोटों के टाइम पर गरीबी हटाओ का नारा होता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप प्रधान मंत्री जी की सोच के अनुसार पूरे बुंदेलखंड में लोगों को अवसर दीजिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को किसी का मोहताज न रहना पड़े, अपने बल पर वहां का आदमी खड़ा हो सके। इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे इन सुझावों पर मंत्री महोदय जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं निषाद जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बुंदेलखंड के बारे में यहां अपना संकल्प प्रस्तुत किया। यह न केवल एक बहुत जरूरी विषय है, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे देश का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट होना चाहिए। अगर आप देखें, तो बुंदेलखंड बेसिकली झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, दतिया और ग्वालियर से मिल कर बनता है। अमूमन मैं इन सभी जगहों पर विस्तार से घूमा हूँ पत्रकार के रूप में और बाद में भी मैं बहुत गया हूँ। निश्चित रूप से बुंदेलखंड की स्थिति 60-70 साल में इतने प्रयासों के बाद भी आज तक संभल नहीं पाई है। मैं एक किस्से से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार हमारे पास बांदा से हमारे एक एमएलए आए और उन्होंने कहा कि साहब, आप हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ मदद करवा दीजिए। तो हमने कहा कि सांसद निधि से करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए, हमें अगर आप पुरानी पहनी हुई धोतियां, साड़िया दिलवा दो तो उससे बड़ा काम चल जाएगा। जो भी हों, हजार, दो हजार, पांच सौ लोगों से मांग कर दिलवा दो। मैंने पूछा - ऐसा क्यों? तो वे बोले कि ज्यादातर गांवों में ऐसी हालत है कि एक धोती से, एक साड़ी से वहां महिला अपना काम चलाती है और जब अपनी साड़ी को या धोती को धोती है तो वह घर में छिपी रहती है। जब वह सूख जाती है तभी पहन कर वह बाहर आती है।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मुझे तब वह किस्सा याद आया, जो महादेव देसाई, जो गांधी जी के सचिव रहे, उनके जो पुत्र हैं, वे सब जगह बापू कथा कहते हैं। उन्होंने यहां पर बिरला हाउस में दो साल पहले कथा की,

तो उसमें उन्होंने किस्सा सुनाया कि बापू ने कोट, आई, अच्छे कपड़े पहनने क्यों छोड़े? वे एक बार ओडिशा में गए। जहां बापू का प्रोग्राम होना था, वहां बा भी उनके साथ गईं। उन दिनों यह तो था नहीं कि मोबाइल फोन हों, टीवी हों, रेडियो हों और उनसे पता चल जाए कि कौन कहां आ रहा है। अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो गांव-गांव टोलियां जाती थीं और बताती थीं कि महात्मा गांधी जी आए हैं, वहां चल कर मीटिंग में आप उनकी बात सुनिए। तो एक घर का दरवाजा कस्तूरबा गांधी जी ने खटखटाया। एक महिला जी ने अंदर से आवाज दी। उन्होंने उससे कहा कि मैं ऐसे-ऐसे आई हूँ, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी आए हैं, कल उनकी मीटिंग है, आप आएंगी? उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगी। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं आएंगी? आप उनको जानती हैं? उसने कहा कि हां, नाम सुना है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। उनके द्वारा काफी पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे पास सिर्फ एक धोती है और वह मेरी बहन पहन कर एक रिश्तेदारी में, शादी में गई है, इसलिए अगले दो-तीन दिन तक मैं घर के अंदर बंद रहूंगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। बा ने आकर यह बात गांधी जी को बताई, तो उनका जो अगला प्रोग्राम मद्रास में बीच पर था, वे वहां गए और यह पूरा किस्सा उन्होंने सुनाया और फिर ऐलान किया कि मैं आज से ये सारे कपड़े त्याग कर रहा हूँ, मैं लंगोटी और यह धोती पहनूंगा। उस दिन से गाँधी जी ने ये चीजें पहनी। जब यह बात उस विधायक विवेक सिंह जी ने मुझे बताई, तो मुझे एकदम वह बात याद आ गई कि क्या यह स्थिति है कि महिलाओं के पास वस्त्र तक नहीं हैं, कपड़े तक नहीं हैं! यह बुंदेलखंड की स्थिति है! हमें लगता है कि उन्होंने जो यह बात रखी है, इतनी चिंता की बात है कि इसकी तरफ हम सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि वहाँ संभावनाएँ नहीं हैं। बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएँ हैं। अगर आप बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहर देखेंगे, तो जैसा रापोलू जी ने कहा था, चित्रकूट तो बहुत बड़ा केन्द्र है। वहाँ भगवान राम रहे थे। वहाँ इतना टूरिज्म हो सकता है कि आप पूछिए मत। वहाँ इतने लोगों को ले जाया, ले आया सकता है। वहाँ पर कामदगिरी पर्वत है, जिसकी परिक्रमा करने हजारों-लाखों लोग जाते हैं। आला ऊदल की सबसे बड़ी वीर गाथाएँ हैं, वे भी बुंदेलखंड से शुरू होती हैं। आपने झाँसी की रानी के बारे में बताया कि वे बुंदेलखंड से आती हैं। वहाँ ओरछा के मंदिर और ओरछा का पूरा इलाका पर्यटन के ख्याल से कितना अच्छा है। बगलामुखी माँ का मंदिर टीकमगढ़ में है, वह बहुत जबर्दस्त है। वह झाँसी के पास है, दोनों बिल्कुल अगल-बगल मिले हुए हैं। वहाँ मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवि थे, जिन्होंने लिखा था, "जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है।" ऐसी ओजस्वी बातें लिखने वाले कवि थे। वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान थीं, जिन्होंने झाँसी की रानी का इतिहास लिखा। उन्होंने लिखा, "बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी"। झाँसी का किला, ओरछा के मंदिर, ओरछा के गेस्ट हाउस, बगलामुखी माता, चित्रकूट, इतनी जगहें हैं। अगर टूरिज्म के हिसाब से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर इनको develop करें, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सिर्फ पर्यटन से आप काफी चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पर ग्वालियर का किला भी है, और भी तमाम जगहें हैं। पर्यटन से बुंदेलखंड की बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। आज क्या हो रहा है? जैसा उन्होंने बताया कि यह नीलगाय के लिए जाना जा रहा है और पहले यह डाकुओं के लिए जाना जाता था। मैं पत्रकार के रूप में anti-dacoity operation cover करता था, तो वहाँ फूलन देवी और दूसरे डाकुओं को cover करने के लिए जाता

[श्री राजीव शुक्ल]

था। उस इलाके में डाकू ही डाकू थे। जहाँ गरीबी होगी, जहाँ भुखमरी होगी, वहाँ डाकू पैदा होते हैं। वह इन चीज़ों के लिए जाना जाता था, बजाय इसके कि वह right reasons के लिए, सही कारणों के लिए जाना, जाना चाहिए था। हमें इस तरफ ध्यान देना है कि हम कैसे उस इलाके को develop करें। तुलसीदास जी, इनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं, वे भी बाँदा से, राजापुर से थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, लेकिन उनको भी चित्रकूट से बनारस जाना पड़ा। उनकी manuscript, पांडुलिपि लिखित रामचरितमानस आज भी राजापुर में उनके गाँव में रखी है। यह हमें ध्यान देना है कि हम कैसे वहाँ का टूरिज्म विकसित करें।

दूसरे, जो वहाँ खेती से जुड़े हैं, वहाँ की समस्या यह है कि वहाँ की खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करती है, वरना पूरा सूखा है। हमें agricultural scientists या agricultural university के जरिए कुछ ऐसा develop करना चाहिए कि सूखे स्थलों में खेती हो सके। कहते हैं कि इसमें इज़रायल की technology बहुत अच्छी है। अगर हम वह technology वहाँ ले जाएँ, जिससे वहाँ खेती की पैदावार बढ़ाई जा सके, जिससे पानी की कम जरूरत पड़े, तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद वहाँ उस तरह की फसलों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वहाँ पर ऐसे agricultural products हों, जिनमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत न पड़ती हो।

तीसरा, मैं बीड़ी उद्योग के बार में बताना चाहूंगा। मानिकपुर का, बाँदा का बीड़ी उद्योग बड़ा जबर्दस्त रहा है। यह उद्योग धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। बीड़ी उद्योग वहाँ के लोगों की lifeline बन सकता है, क्योंकि तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। पूरे देश में इसकी सप्लाई हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ का region इसका फायदा ले रहा है, लेकिन बुंदेलखंड इसका फायदा नहीं ले पा रहा है।

चौथी चीज़ उद्योग में प्राथमिकता की है। कहा बहुत गया, लेकिन वहाँ industry नहीं लगी। जब राहुल जी वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने काफी दौरा करके कोई 7 हजार करोड़ रुपए का पैकेज बुंदेलखंड को दिलाया था, लेकिन होता यह है कि यह सब bureaucracy के through जाता है, तो हर बार जितने पैकेज दिए जाते हैं, सब कहीं न कहीं गड़प हो जाते हैं। राज्य सरकारों के जरिए पैकेज चलते हैं। जैसा हमारे पाटिल साहब ने भी कहा कि पैकेज का लाभ सही ढंग से पहुँचना चाहिए और नीचे उसकी monitoring होनी चाहिए। अगर उसकी monitoring नहीं होती है, तो पैकेज का कोई लाभ नहीं होता है।

अभी इन्होंने एक सिंचाई की सुविधा वाली बात कही। वहाँ यमुना नदी बहती है। इतनी बड़ी नदी है कि उसी से इतनी सिंचाई हो सकती है कि पूछिए मत। बेतवा है, बेतवा में बाढ़ आ जाती है, तो पार करना मुश्किल होता है। इन्होंने केन नदी के बारे में भी बताया। कम से कम इन नदियों की वहाँ garlanding हो सकती है, एक माला बनाई जा सकती है और पूरे इलाके को सिंचाई के द्वारा हरा-भरा किया जा सकता है। जब मैं प्लानिंग कमीशन में था, तो मैं KBK region के बारे में सोचता था कि KBK region में बुंदेलखंड को भी शामिल करना चाहिए और इसको KBBK region करना चाहिए। वह आसानी से हो सकता है। उसके लिए special concession, special package दिया जा सकता है।

आप एक चीज जान लीजिए कि अगर tax benefit मिलता है, तो industry अपने आप वहाँ भाग कर जाती है। महोदय, जहाँ इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल पैकेज मिलता है, वहां उद्योगपति इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए भाग कर पहुंच जाते हैं। जैसे असम में इंडस्ट्रीज़ को विशेष पैकेज मिला, वहां बहुत उद्योगपति पहुंच गए। इस तरह से अगर वहां benefits दिए जाएं, तो बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका बन सकता है, एक ऐसा आकर्षण का केन्द्र बन सकता है, एक ऐसा destination बन सकता है, जिससे कि लोग वहां जाएंगे। इससे उस क्षेत्र की तरक्की और विकास होगा।

महोदय, मैं श्री विशम्भर प्रसाद जी का फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह के विषय को संसद में लाकर इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाया है। धन्यवाद।

श्री जयराम रमेश (कर्णाटक): सर, वहां श्री राजीव शुक्ल जी एक क्रिकेट स्टेडियम बनवा दें, तो उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल: महोदय, जब श्री जयराम रमेश जी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए आपका धन्यवाद। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जिस ज्वलंत समस्या को उठाने का काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। वे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी रहे हैं और वहां के मंत्री भी रहे हैं और उन्हें बुंदेलखंड के एक ऊर्जावान नेता के रूप में भी जाना जाता है। अभी आदरणीय राजीव शुक्ल जी सच कह रहे थे कि उसे इस नाम से जाना जाता था कि 'बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।' झांसी की रानी के किस्से की स्थिति यह हो गई कि लोगों ने अपनी नाम के आगे 'बुंदेला' लिखना शुरू कर दिया। राजाओं ने अपने नाम के आगे बुंदेला लिखना शुरू कर दिया, लेकिन वह क्षेत्र आज भुखमरी के कगार पर है। जमीनें सूख चुकी हैं। उनके ऊपर पपड़ी आ चुकी है और जमीनें जिस प्रकार से सूखी हैं, उसी प्रकार से वहां कि किसानों की आंखें भी सूख और पथरा गई हैं। वहां का किसान आसमान की तरफ हाथ उठाकर कभी देखता है और कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कभी 10 बूंद पानी हमें दे दो, ताकि उस पानी से हम अपना जीवन जी सकें और पृथ्वी जो तृषित है, उसे भी सींचने का काम कर सकें, लेकिन यह नहीं हुआ।

मान्यवर, यह स्थिति कोई एक वर्ष से नहीं है। अगर देखा जाए, तो पिछले लगभग 20 वर्षों से यह स्थिति है, जिसे कि पूरा का पूरा बुंदेलखंड झेल रहा है और जूझ रहा है। मुझे ध्यान है कि मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उस समय था, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्य मंत्री, माननीय कल्याण सिंह जी बने थे। उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में तीन निधियों की घोषणा की थी। उसमें उन्होंने बुंदेलखंड विकास निधि की बात भी कही थी और तब केवल 10 करोड़ रुपए से बुंदेलखंड विकास निधि की बात तय की थी। उस समय पूर्वांचल विकास निधि, मध्यांचल विकास निधि और बुंदेलखंड विकास निधि, इन तीन निधियों की बात उन्होंने कही थी। उसी के बाद, वे निधियां धीरे-धीरे बढ़ती गईं। उस समय इन निधियों की घोषणा इसलिए की गई थी कि उस वक्त भी वहां के जनप्रतिनिधि विकास के

[श्री शिव प्रताप शुक्ल]

कामों को कराने के लिए परेशान थे। वे वहां कुछ विकास के काम करना चाहते थे। उस समय 'विधायक निधि' भी नहीं हुआ करती थी। इसलिए इस निधि के द्वारा ही हम अपने क्षेत्र का कुछ विकास करा सकें, इस आधार पर उन्होंने इन निधियों की घोषणा की थी।

महोदय, आज बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी है। हम किसी सरकार को दोषी नहीं बताएंगे, किसी सरकार को कोसने का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम सभी लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी लोग मिल कर के बुंदेलखंड के विकास के संदर्भ में सोचें। जहां इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोग कभी भी प्राणों की बाजी लगाने में हिचकते नहीं थे, अपना खून देने में हिचकते नहीं थे, आज वहां जल के बिना पृथ्वी सूखी है, लेकिन लोगों ने उस पृथ्वी को अपने खून से सींचने का काम किया है। इस प्रकार का बुंदेलखंड का इतिहास रहा है और लगता है कि वही खून ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह सूख गया है और पपड़ी की तरह हो गया है। उस खून को हमने इस देश को आजाद कराने के लिए बहाया था। वह आज हमें पुकार रहा है। हमें उधर चलने की आवश्यकता है। आज जब हम उस पर विचार करें, तो हम यह नहीं कहेंगे कि तेंदू के पत्ते के आधार पर बीड़ी का उद्योग डेवलप किया जाए, क्योंकि कभी बीड़ी का उद्योग बहुत अच्छा डेवलप्ड था, लेकिन चूंकि वह नशे से संबंधित है, इसलिए हम वह नहीं कहेंगे। लेकिन, तेंदू के पत्ते का उपयोग वहाँ बहुत है। पहले वहाँ जंगल के किनारे रहने वाले लोग जंगल में जाते थे, तेंदू के पत्ते बीनते थे, तोड़ते थे, उनको ले जाते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। उससे उनका जीविकोपार्जन हो जाता था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि जो लोग कभी तेंदू के पत्तों को बेचकर रोटी खा लेते थे, वे आज वहाँ की सूखी हुई घासों को पीसकर, उसकी रोटी बनाकर किसी तरह से अपने और अपने बच्चों के पेट पालने का काम करते हैं। घास की रोटी के बारे में कभी आदरणीय महाराणा प्रताप जी के संदर्भ में कहा गया था, जिन्होंने लड़ाई लड़ते हुए जब यह देखा था कि उनके बच्चों को घास की रोटी दी जा रही है, तब उनकी आँखें डबडबा गई थीं। जब तक वे कोई दूसरा निर्णय कर पाते, तब तक वहाँ भामाशाह जी पहुँच गए थे। भामाशाह जी ने जो त्याग और बलिदान दिया, उसका परिणाम था कि महाराणा प्रताप एक बार पुनः इतिहास के एक कलंकित पुरुष होने से बच गए। इस नाते हम सभी लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, हम कहना चाहेंगे कि पिछले 15-20 वर्षों से वहाँ के किसान परेशान हैं। अगर हम केवल 5 वर्षों का रिकॉर्ड देखें – विशम्भर जी भी इससे सहमत होंगे, जो काम किया है, खनन माफियाओं ने लूटा है। अगर उन खनन माफियाओं के लूटने के केवल 5 वर्षों के इतिहास को खत्म कर दिया जाए, उनकी निधि को लाया जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में कम से कम 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपये आते। मान्यवर, एक-दो करोड़ नहीं, बल्कि 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपये केवल 5 वर्षों में खनन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश के बालू और मोरंग से लूटने का काम किया। वह पैसा खज़ाने में जमा नहीं हुआ, लेकिन उससे उनकी जेब खूब भरी।

मान्यवर, एक दिन मैं गोरखपुर से आ रहा था और गोरखपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। तभी मैंने सुना कि वहाँ की एनाउंसर एनाउंस कर रही थी कि अगर हम लोग रेलवे को बचा लें, हम लोग सच्चाई के साथ चलें, हम लोग ईमानदारी के साथ चलें, तो हम रेल की पटरी को सोने की पटरी

में बदल सकते हैं। वह एनाउंस कर रही थी कि हम अगर ईमानदार हो जाएँ, सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो निश्चित रूप से रेलवे की इतनी कमाई हो सकती है कि हम सोने की पटरी बना सकते हैं। मान्यवर, यह एक उदाहरण है। सोने की पटरी पर रेल नहीं चल सकती है, लेकिन उसने यह कहा कि अगर हममें सच्चाई आ जाए, जो हम लोहे को भी सोना बना सकते हैं। चाहे केन्द्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आज हम सभी सरकारों से यह कहना चाहते हैं, कि सभी को बुंदेलखंड के लोगों की तृष्णा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, मैं इस संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर के रहने वाले थे और उन्होंने वहाँ के दुःख और दर्द को जाना था, इस नाते उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना - नदी जोड़ो परियोजना की बात कही थी। वह उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। आज मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने निर्देश दिया और उस निर्देश का परिणाम हुआ कि जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए डीपीआर जारी किया और उस डीपीआर को उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये के रूप में जारी करने का काम किया है। मान्यवर, इसी 20,000 करोड़ रुपये से, जिसकी बात हम सब लोग कह रहे हैं कि बिना सिंचाई के, बिना पानी के न तो बुंदेलखंड का सूखा दूर हो सकता है, न तो बुंदेलखंड के किसानों की हड्डियों के ऊपर माँस चढ़ सकता है, उनकी जो आँखें पथरा गई हैं, न तो उनमें आँसू आ सकते हैं। वहाँ खुशी आ सकती है और यह तभी होगा जब बुंदेलखंड को हम पूरी तरह से सिंचाई से आच्छादित कर देंगे। छतरपुर की बात अभी यहां आदरणीय राजीव जी ने कही। वहां एक राम राजा का मंदिर है। झांसी में पूरी धरती सूखी हुई है, लेकिन झांसी से ज्यों ही बाहर जाते हैं, वहां हमें तत्काल बहती नदी दिखाई पड़ती है। उस नदी में इतना निर्मल पानी है कि देखते ही लगता है कि भले ही हम घर से नहाकर आए हैं, चलो, इस नदी में कूदकर एक बार नहा अवश्य लें, जल से नहाकर ठंडापन तो महसूस कर लें। अभी जिस महत्वूर्ण योजना को भारत सरकार ने देने का मन बनाया है, उसके पूरा होने में, मैं मानता हूं कि समय लग सकता है, क्योंकि एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने का जो DPR भारत सरकार ने बनाया है, उसके आधार पर निश्चित रूप से, हम कह सकते हैं बुंदेलखंड की सूखी धरती को सिंचाई देकर हरा-भरा बना देंगे और लोगों की समस्याएं दूर कर पाएंगे।

भारत के प्रधान मंत्री जी अभी बुंदेलखंड गए थे। वहां उन्होंने कहा कि हम बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन करेंगे। अगर बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन हो जाता है, तो केवल वहां सिंचाई ही उपलब्ध नहीं होगी, जो अन्य खनिज उपलब्ध वहां हैं, वे भी सुरक्षित हो जाएंगे, पारम्परिक विकास होगा, वहां की संस्कृति बचेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये सारे के सारे उपक्रम एक साथ भारत सरकार बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन करने के बाद दे पाएगी। यह सही है कि आज अनेक लोग बुंदेलखंड छोड़ने के लिए मजबूर हैं। स्थिति यहां तक खराब है कि अपने शरीर को बचाए रखने के लिए, प्राण बचाने के लिए, लोग अपने बच्चों को शहरों में बेचकर चले आते हैं। विशम्भर जी ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है, हमें बड़ी गम्भीरता के साथ उस पर विचार करना पड़ेगा। ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, मुझे थोड़ा समय दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): अभी आपके दो स्पीकर शेष हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: हमने थोड़ा उपक्रम किया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सम्पूर्ण भारत में गरीबों की बदहाली दूर करने के लिए उनके जन-धन खाते खुलवाए। उनमें व्यवस्था की गई कि गरीब एक पैसा लगाए बिना खाताधारी भी बन सकता है, रुपए वाला भी बन सकता है और ऊर्जावान भी बन सकता है। उन्होंने एक हजार और 500 रुपए के नोटों को बंद करके लोगों के जन-धन खाते में खजाना डालने का काम किया। जो लोग दुनिया भर के पैसे रखे हुए थे, गांव के लोगों के खाते में उन्होंने वे रुपए बिना शर्त के डाल दिए कि हम बाद में किसी तरह ले लेंगे। लेकिन वह ऐसी निधि थी, उसमें ऐसी शर्त थी कि खाते से पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। जन-धन खातों के आधार पर अनेक गरीब लखपति बन गए। वे पैसा भले ही न निकाल सकें लेकिन अपने खाते के आधार पर लखपति होने का गर्व महसूस कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है। ऐसे अनेक खाते बुंदेलखंड में भी खुले होंगे। उज्जवला योजना के अंतर्गत दो करोड़ से अधिक लोगों को पूरे भारत में लाभ मिला। मैं कह सकता हूं कि 60,000 से अधिक गैस सिलिंडर्स, माननीय प्रधान मंत्री जी की इस योजना के अंतर्गत, अकेले बुंदेलखंड में बांटने का काम हुआ है। वे लोग जो पहले जंगलों से लकड़ियां काटकर लाते थे, बेचते थे और उसी से भोजन बनाते थे, उन लोगों की रसोई में आज गैस से खाना पकाने का काम हो रहा है। यदि सरकार की ऐसी सोच होगी तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का विकास हो सकता है - चाहे वह मराठवाड़ा का इलाका हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या कर्णाटक का इलाका हो, जिसकी चर्चा अभी की गई। सभी क्षेत्र इससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। मान्यवर, आप सोचिए और विशम्भर जी भी इस बात से सहमत होंगे कि बुंदेलखंड से केवल एक दिन में 25 से 30 करोड़ रुपए खनन में जाते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में विकास करने लगें, तो कितना फायदा होगा? अभी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है। हम वहाँ की सरकार से भी यह माँग करते हैं कि खनन माफियाओं के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर उत्खनन के कार्य से किसी को जोड़ना है, तो वहाँ के निषाद बन्धुओं को जोड़ना चाहिए, वहाँ रहने वाले लोगों को जोड़ना चाहिए, जिससे वहाँ का फायदा हो सके और वहाँ के लोग भी रोजगार पा सकें।

मान्यवर, यहाँ माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं और वे जवाब भी देंगे। मैं जानता हूँ कि वे बहुत ही यशस्वी कृषि मंत्री हैं और ये पूरे तौर पर अपनी तैयारी में थोड़ी और वृद्धि कर लें और बुंदेलखंड के ऊपर आज इतनी अच्छी बात कह दें, जिससे यहाँ के लोग, जो उन किसानों की आँखों के आँसू अपनी आँखों में लेकर रो रहे हैं, इनकी आँखों के आँसू भी न सूखें, बल्कि वे खुशी बनकर चले आएँ। मैं आदरणीय कृषिं मत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि भारत सरकार की जो अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो बुंदेलखंड के लिए वह तैयार कर रही है, उन योजनाओं का वे यहाँ वर्णन करें, ताकि हम लोग खुशी-खुशी बुंदेलखंड में जाकर वहाँ के लोगों से यह कह सकें कि अब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की नई सरकार, ये दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के विकास की पूरी संकल्पना को रचेंगी, वहाँ के लोगों को अब भूखा नहीं सोने देंगी, लोगों की आँखों के आँसू देर करेंगी, लोगों की बदहाली दूर करेंगी और उस जमीन पर पूरे तौर पर हरा-भरा करने का काम करेंगी, जो मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। दोनों राज्यों के अंदर सात-सात जिले हैं, लेकिन एक प्रदेश के सात जिले हरे-

भरे लग रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के दूसरे सात जिले सूखे हैं। ये दोनों सात-सात जिले हरे-भरे हों, लहलहाते रहें और बुंदेलखंड भी लहलहाए और एक बार पुनः वहाँ का बुंदेला कह सके कि फिर किसी बात की जरूरत होगी, तो हम अपना खून बहा देंगे। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राज बब्बर (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विशम्भर प्रसाद जी को बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वे बुंदेलखंड का इतना महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर यहाँ आए। जिस संकल्प को लेकर आप यहाँ आए हैं, वह संकल्प सही मायने में आज से नहीं बल्कि सदियों से यह माँग भी करता रहा है, चाहता भी रहा है। पौराणिक जमाने से लेकर आजादी की लड़ाई तक इस बुंदेलखंड को पहचाना गया, इसको जाना गया, लेकिन आज वह बुंदेलखंड, जिसने एक पौराणिक आस भरी थी, एक उम्मीद की थी कि भगवान राम, जो वनवास काट रहे थे, वे दोबारा राजा बन जाएँ, उसकी वह उम्मीद पूरी हुई और सारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर राजा राम का कहीं कोई मंदिर है, तो बुंदेलखंड के अंदर है।

यह वह बुंदेलखंड है, जहाँ पर आजादी का अलख जगाने के लिए झांसी की रानी और बख्त खान ने जब एक संकल्प लिया और आजादी की उस जंग को लड़ने के लिए उस अलख को लेकर निकले। एक तरफ तलवार थी और दूसरी तरफ तराना और रोटी थी। जब वे लोग ये लेकर इस देश को आजाद कराने के लिए पहुँचे, तो देश आजाद हुआ। आज फिर से बुंदेलखंड आजादी की वह राह देखना चाहता है, वह खुशबू देखना चाहता है, वह महक सूँघना चाहता है, लेकिन कभी बुंदेलखंड की तरफ हम जाते हैं, तो बहुत दुःख होता है। आज केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, तीनों सरकारें गौरक्षा को लेकर एक सोच के साथ चल रही हैं। आज अपने दिल पर हाथ रखकर यह कहना पड़ रहा है कि बुंदेलखंड की सड़कें वे सड़कें हैं, जिन सड़कों पर आज गौ माता ज्यादा से ज्यादा ट्रकों से accident होने के बाद सड़कों पर हताहत पड़ी होती हैं और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होता है। बुंदेलखंड की सड़कों के अलावा शायद पूरे भारत में इससे ज्यादा गायें कहीं हताहत नहीं होतीं। दुर्भाग्य है, घर में खाना न होने की वजह से जितने नौजवान हैं, वे घर छोड़कर चले गए हैं, जितने बुजुर्ग हैं, वे घरों में हैं। अगर गांव के अंदर चले जाएं - मुझे याद है, मैं 2008 के बाद जब बुंदेलखंड की तरफ गया था, तो मैंने गांव के अंदर जाकर देखा कि गांवों के गांवों में ताले लगे हुए हैं। एक घर में सिर्फ एक बुजुर्ग बैठा है, बाहर कहीं बूढ़ा बाप और कहीं बूढ़ी मां बैठे हैं। ऐसी स्थितिमें वहां लोग अपने बुजुर्गों को छोड़कर चले जाते हैं - अगर वे बीमार होंगे तो उन्हें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, इसका किसी को एहसास नहीं है, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के लिए चले जाते हैं। उन बुजुर्गों के चेहरे पर अपने परिवार के किसी नौजवान बच्चे के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि वे चले गए हैं, हम तो देख ही लेंगे। वहां पर उन बुज़ुर्गों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं होता है। आज विडम्बना है कि जिस बुंदेलखंड के, जिस चित्रकूट के बारे में अभी कहा गया कि:

"चित्रकूट के घाट पे, भई संतन की भीर,
तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर।"

मुझे लगता है कि आज वहां पर तिलक करने के लिए सिर्फ तीज-त्योहारों पर माथे रह गए हैं -

[श्री राज बब्बर]

4.00 P.M.

शायद घिसने के लिए चंदन और उस पानी की महक खत्म होती जा रही है। जिस तरह से आज वहां पर माफिया का हाल है, वहां पर कृषि माफिया है, एक तेन्दू पत्ते का business होता है, वहां पर उसकी बहुत बड़ी पैदावार है। उस तेन्दू पत्ते की पैदावार सिर्फ माफियाओं के हाथ में है या उन लोगों के हाथ में है जो दबंग होते हैं। यहां तक कहा जाता है कि शायद डाकू उस पर राज करते हैं। एक तरफ वहां पांच-पांच नदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद यह बात बिल्कुल सही है कि वहां का मैनेजमेंट नहीं हुआ। उसके कारण शायद और भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां का माफिया तंत्र इतना बड़ा तंत्र है - चाहे वह मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो - उनकी सीमाएं आपस में इतनी लगी हुई हैं कि वह तंत्र पूरी तरह से अपनी दबंगई करता है, मध्य प्रदेश वाला दबंगई करके उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाता है और उत्तर प्रदेश में दबंगई करके मध्य प्रदेश में चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी दबंगई कायम रहती है और वहां पर जो मज़दूर हैं, वे गुलामों की तरह काम करते हैं। ऐसी हालत में राहुल गांधी जी ने वहां पर interior में जाकर देखा, वे लोगों से मिले, उनसे बातचीत की। यह किसी पार्टी की बात नहीं है, यह संवेदना की बात है। उन्होंने उस वक्त की यूपीए सरकार से कुछ ऐसे प्रावधान निकाले कि 7,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज वहां पर गया। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या वजह थी, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वह 7,000 करोड़ रुपया सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आया, जिनकी इंडस्ट्री आज भी वहां पर बहुत फल-फूल रही है और वह इंडस्ट्री है, माफियाज़ की - रेत माफिया, एक से एक बड़ा पैसे वाला, एक से एक धनाड्य, एक से एक दबंग और मज़बूत आदमी। इन लोगों से मुकाबला करने के लिए आज केन्द्र सरकार, महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मत्री महोदय से कहना चाहूंगा, सरकार से भी कहना चाहूंगा कि ऐसा पैकेज नहीं, बल्कि ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि जिस बुंदेलखंड को हम राम के लिए मानते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम को लेकर हम पूरे देश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह चुनावी माहौल हो या किसी भी तरह का माहौल हो।

उस माहौल को जिंदा रखने के लिए कम से कम जहां-जहां से राम गुजर कर आए हैं, उनका भी सम्मान करना शुरू करें। जहां-जहां राम रहे हैं, उसका भी उतना ही सम्मान करें और सम्मान करने का स्थान अगर कहीं मिलता है, तो वह बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड के अंदर आज जरूरत है कि किस तरह से सिंचाई के साधन पैदा किए जाएं। आज दोनों प्रदेशों में एक ही पार्टी की सरकार है, दोनों प्रदेशों की सरकारें मिलकर वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाएं। बुंदेलखंड को यह न समझा जाए कि यह दूसरा प्रदेश है, यह इसका प्रदेश है और वह उसका प्रदेश है। आज इसको प्रदेशों की सीमाओं में न बांधकर वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं। यह बात बिलकुल सही है कि दान नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाया जाएगा, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। वहां पर माहौल बनाया जा सकता है। वहां पर माफियाओं के ऊपर ईमानदारी से सख्ती की जाए। वहां पर उनकी दबंगई को रोकने का काम किया जाए। वहां पर उनकी ताकत को रोका जाए, जिसकी वजह से गरीब आदमी आज भी अपने गांव को छोड़कर बाहर जा रहा है। गरीब आदमी के पास अपने लिए खाने को अन्न नहीं है। उसके पास अपने जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं है। वह अपने जानवरों को बाहर

छोड़ देता है और वे सड़कों पर घूमते रहते हैं। वे जानवर रात को खूंटे पर या तो अपने आप चले आते हैं या उनको बांधकर ले आया जाता है। इस तरह से वहां पर बहुत से हादसे होते हैं, वहां पर जानवर, मवेशी मर रहे हैं। वहां पर नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है। वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। इस सब के लिए जरूरी है कि वहां का विकास हो। वहां पर बहुत जमीन है, वहां पर बहुत विकसित जमीन है, उस जमीन को सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाई जाए, उसके लिए एक स्वरूप बनना चाहिए। साथ ही साथ वहां की जो कानून व्यवस्था है, उसके लिए दोनों ही प्रदेशों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और केन्द्र सरकार इस पर निगरानी रखकर बुंदेलखंड को उसका सौंदर्य, उसका शौर्य दोबारा वापिस करे, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): धन्यवाद राज बब्बर जी। आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है। महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया जी।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात): सर, वैसे तो मैं गुजरात से राज्य सभा सांसद हूं, मगर आज मेरी पार्टी ने इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। हमारे आदरणीय सदस्य विशम्भर प्रसाद निषाद जी बुंदेलखंड के संबंध में जो प्राइवेट मेम्बर बिल लेकर आए हैं, जो संकल्प लेकर आए हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। इस संकल्प में उन्होंने किसानों के हित की बात कही है। किसानों को होने वाली समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा है। किसान जो समस्याएं झेल रहे हैं, जो पीड़ा झेल रहे हैं, जिस पीड़ा को वे सहन कर रहे हैं, उन बातों को रखते हुए उन्होंने कुछ मांगें और संकल्प रखे हैं, जिसमें बातें दूसरी तरह की दिखाई दे रही हैं। उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योग की बात रखी, केन्द्रीय पुलिस बल की बात रखी, बिजली की मांग की बात रखी, वृद्ध पेंशन योजना की बात रखी, शिक्षा संबंधी सुविधा की मांग रखी, बीपीएल कार्ड की मांग रखी, निशुल्क आवास एवं शौचालयों की बात रखी। वास्तव में यहां पर सभी सांसदों ने बुंदेलखंड के किसानों के बारे में चिंता जतायी, तो मैं कहूंगा कि किसान समस्याओं को झेल रहा है, वह पानी के अभाव को भी झेल रहा है। अकाल और सूखा पड़ने का कारण क्या है, उस विषय पर हमें ध्यान देना होगा। माननीय सदस्य जी ने दूसरी बात यह भी रखी कि नीलगायों की बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए बनी हुई है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहता हूं। जहां पर गाय शब्द का प्रयोग होता है, वहां इस देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले हिंदू लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय जुड़ जाता है। हमने कई ऐसे किस्से सुने व देखे हैं कि किसान अपने खेत में काम करने जाता है, वहां जंगल में कोई नीलगाय बच्चा पैदा करती है, लेकिन कोई शिकारी उसका शिकार कर देता है और वह नीलगाय मर जाती है। तब उस का बच्चा किसान के हाथ लग जाता है और किसान के घर की गाय जो अपने बछड़ों को पोषण देती है। इस तरह ऐसे जानवरों को पालने का पवित्र कार्य इस देश का किसान कर रहा है, लेकिन हम यहां अपने सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने वाली कई घटनाओं का जिक्र सुनते हैं। सर, अकाल और सूखे का वास्तविक कारण जंगल की कटाई है, नदियों से बालू और अवैध रूप से निकाला जाना है, जंगल में हरे-भरे वृक्षों की बेतहाशा कटाई है, वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमारी नीरसता है और जल-संचय अभिगम की जागरुकता के संबंध में हमारी नीरसता है। सर, हमारे आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब गुजरात की जनता के सामने भी यही प्रश्न था, गुजरात के किसानों के सामने भी यही समस्या थी, लेकिन आज गुजरात लहलहा रहा है। गुजरात में कहीं कोई समस्या नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): आप को नर्मदा का पानी दिया है।

महंत शम्भुप्रसाद जी तुंदिया: सर, नर्मदा का पानी आपने दिया, लेकिन नर्मदा के पानी के लिए हमारे आज के प्रधान मंत्री जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उसके लिए उन्होंने 72 घंटे का उपवास और अनशन किया था, तब जाकर केन्द्र की सरकार ने नर्मदा के पानी के लिए मंजूरी दी थी। आज आप हमारे गुजरात में आइए, एक भी किसान ऐसा नहीं है जिस के घर में four wheeler न हो। हरेक किसान का बच्चा आज two wheeler लेकर घूम रहा है। सर, अगर हम 15-20 साल पहले की गुजरात की स्थिति देखें, तो उस की भी स्थिति दयनीय थी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि उस समय जब आदरणीय नरेन्द्र भाई गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने एक सूत्र दिया था, "खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में।" उनकी सरकार के समय किसानों के हित के लिए "कृषि मेले" लगवाए गए और हर साल "कृषि महोत्सव' हुए। सर, जून-जुलाई में हरेक विधायक को अपने क्षेत्र में 15-15, 20-20 दिन तक वहां रुकने को कहा जाता था। इस तरह हर गांव में जाकर हम किसान की जागरूकता और जल-संचय अभिगम के लिए कार्य करते थे। आज उसी का परिणाम है कि भारत की पैदावार में सब से ज्यादा कृषि दर में वृद्धि गुजरात में मिल रही है। गुजरात का किसान आज सब से ज्यादा विकास दर प्राप्त कर रहा है।

सर, मैं बुंदेलखंड के विषय में कहना चाहूंगा और जैसा कि मेरे एक पूर्व साथी ने बताया कि बुंदेलखंड 14 जिलों का है, लेकिन उस में 7 जिले उत्तर प्रदेश और 7 जिले मध्य प्रदेश में हैं। उस से यह बात उभर कर आयी है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किसान की आमदनी और स्थिति अच्छी है। तो ऐसा क्या है कि यू.पी. के 7 जिलों वाला बुंदेलखंड पिछड़ा रह गया है? अभी हमारे आदरणीय बब्बर साहब ने कहा कि भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा खनन और भू-माफिया राज भी इस का एक कारण है। सर, मैं आज बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद तुरंत ही जनता के लिए हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई का संदेश दिया है कि मैं इस राज्य का प्रधान सेवक हूं और उन्होंने कायदा और प्रशासन की सुव्यवस्था के लिए अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करवाया। उसी तरह हम सभी सदस्य यह अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अवैध रूप से चलने वाले कामों को ताबड़-तोड़ बंद करवाने का अच्छा काम किया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले भाग में भी भू-माफियाओं का राज चल रहा है, वहां भी वे वही काम करेंगे। जो अवैध रूप से खनन करने वाले लोग हैं, नदियों की सुन्दरता को लूटने वाले लोग हैं और जो देश की खनिज सम्पदा को लूटने वाले लोग हैं, उनको भी वे उसी तरह से दंडित करेंगे। माननीय सदस्य बुंदेलखंड के लिए जो यह संकल्प लेकर आए हैं, मैं इसके लिए यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय आदित्यनाथ जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और केन्द्र में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, इन्होंने यहां से भी पहली बार 'फसल बीमा योजना' लागू की है, नीम कोटेड यूरिया की बातें आई हैं और कई तरह की अलग-अलग बातें आई हैं। हमारी आदरणीय मंत्री उमा भारती जी ने नदियों को जोड़ने की योजना, सोलर ऊर्जा पम्प की बात की है। सर, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। केन्द्र सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं हैं, मगर मैं इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से यह

कहना चाहता हूंकि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हैं। इस पंचायत के माध्यम से अगर हम देश की जो सम्पदाएं हैं, जो देश में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए - अगर किसान को ज्यादा महत्व देकर, उसके ऊपर पोषित जो भी है, हमारा किसान क्या है? किसान के लिए तो वह अन्नदाता है। कहतें है कि एक समय में भारत, 'सोने की चिड़िया' कहे जाने वाला देश किसानों के लिए, पूरे विश्व में सबसे सम्पन्न और सबसे आर्थिक व समृद्ध देश था, यह सभी जानते हैं। आज यह देश किन-किन कारणों से पिछड़ा रह गया है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। माननीय सदस्य यहां जो बुंदेलखंड की बातें लेकर आए हैं, इनका सेन्टर तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया और अच्छे विचार रखे हैं, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जितनी भी बातें रखी जाती हैं, जागरूकता करनी चाहिए, जंगल की रक्षा करनी चाहिए, नदियों की रक्षा करनी चाहिए और आजकल पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन कितना ज्यादा temperature बढ़ गया है। अगर हम इस सर्वोच्च सदन से इस देश की जनता को अच्छा संदेश देना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम सबको इस विषय में जागरूकता लानी चाहिए, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री दिग्विजय सिंह, आपके लिए पांच मिनट का समय है।

श्री दिग्विजय सिंह: सर, बुंदेलखंड का इतना गंभीर विषय है और आप हमारे मध्य प्रदेश के होने के नाते - उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का शामिल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय देने की कृपा करें।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप शुरू कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं विशम्भर प्रसाद निषाद जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने आज बुंदेलखंड की बात सदन में रखी है। बुंदेलखंड की अपनी एक संस्कृति है, अपना इतिहास है। आधा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में है। चित्रकूट की परिक्रमा दो-तिहाई मध्य प्रदेश में है और एक-तिहाई उत्तर प्रदेश् में है, इसलिए इस प्रांत की पुरानी मांग तो चली आ रही है, लेकिन मूल रूप से इसके विकास के लिए, जहां इसका प्राकृतिक सौन्दर्य है, वहीं संसाधनों की कमी नहीं है, वन, खनिज, कृषि, जल, उद्योग, पर्यटन कोई आधार मानकर हम इस इलाके का विकास कर सकते हैं। इसी बात को समझकर यूपीए के माननीय राहुल गांधी जी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध किया था कि विशेष तौर पर बुंदेलखंड पैकेज दिया जाए और लगभग साढ़े आठ हजार करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज दिया गया।

महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ वह पैकेज दिया गया था, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई और उसका भारी दुरुपयोग हुआ। वहां की योजना बनाने में कोई बहुत बड़ी रिसच की जरूरत नहीं है। वनों की कटाई के बाद जिस प्रकार से भूजल का दोहन हुआ है, वहां पर केन और बेतवा नदियों पर बांध बने हैं... उससे लाभ भी हुआ है। केन-बेतवा लिंक केनाल भी बनाई जा

[श्री दिग्विजय सिंह]

रही है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार को बुंदेलखंड के मामले में अलग से योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बुंदेलखंड को इसके लिए जो पैकेज दिया गया था, उसका मूल्यांकन तो कराएं ही, साथ ही उसमें इस बात पर भी अधिक ध्यान दें कि उसकी जितनी भी इनकंप्लीट योजनाएँ हैं, जो अपूर्ण सिंचाई योजनाएँ हैं, जिनको पूरा करने की हमारी सरकार की भी नीति थी और आपकी सरकार की भी नीति है, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए।

मैं साथ ही यह भी कहूंगा, मैं इसके बारे में पूर्व से ही कहता आया हूं कि हमें इस बात से सीखना चाहिए कि पूर्व में, बुंदेलखंड में चंदेली राज के समय में जो चंदेली तालाब बने थे, जो कि वाटर कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े माध्यम थे, आज सिल्ट जमा होने की वजह से अधिकांश तालाबों की क्षमता कम होती चली जा रही है। नरेगा के माध्यम से उनकी सफाई की योजना होनी चाहिए थी।

हम लोगों ने, मेरे कार्यकाल में, इसका विशेष ध्यान रखा था और प्रत्येक तालाब पर मछली पालन की व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर मछली पालन के उद्योग का काफी बड़े पैमाने पर प्रचलन है। हमने वे अधिकार मछुआरों को दे दिए थे, वहाँ से ठेकेदारों को अलग कर दिया था और इसको मछुआ पालन की सहकारी समितियों को दे दिया था। हमने उसमें, सहकारी समिति में इस चीज को बाध्य कर दिया था कि, जब तक कोई मछली पकड़ने के लिए पानी में नहीं घुसेगा, वह उसका सदस्य नहीं बन सकता है। इसकी वजह से सब ठेकेदार अलग हो गए थे और मछली पकड़ने वालों को ही शुद्ध लाभ मिला था।

हमने विशेष तौर पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की योजना प्रारंभ की थी। आपके सौराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था। जो सरप्लस वाटर होता है, उसको कुओं में डालकर वाटर रिचार्ज की व्यवस्था की गई थी। मैं आपको इतना बता दूं कि जब नरेन्द्र मोदी जी मुख्य मंत्री बने थे, तब उससे पहले से ही मध्य प्रदेश में, "खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में", जल संसाधन का कार्यक्रम, मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश में चल रहा था। शायद उसी से सीखकर माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने उसकी योजना गुजरात में ली होगी। ...(**व्यवधान**)...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः यह गुजरात में हुआ। ...(**व्यवधान**)... गुजरात में यह योजना सफल रही।

श्री दिग्विजय सिंहः मैं आपको बता रहा हूं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)ः प्रधान मंत्री बनने से पहले आठ बरस से दूसरे मुख्य मंत्री थे, उससे पहले आप थे।

श्री दिग्विजय सिंहः जी, मैं वही कह रहा हूं। वहाँ पर "खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में" की मेरी योजना सन् 95 से प्रारंभ थी। नरेन्द्र भाई वहाँ पर अखिल भारतीय जनता पार्टी के महा मंत्री थे। उन्होंने वहाँ पर उस योजना का तीन साल तक अध्ययन भी किया था।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर खनिज संपदा का भी महत्व है। मेरे मित्र भाई राज बब्बर जी ने सही कहा है कि आज पूरे देश में रेत खनन की जो इल्लीगल माइनिंग हो रही है, यह इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि एक माफिया ऑपरेशन चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो कई अधिकारी लोग मारे जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं। मैंने मध्य प्रदेश में पंचायतों को रेत खनन करने का अधिकार दे दिया था। पंचायतें ठेका देती थीं, राज्य सरकार उसमें नहीं आती थीं, उससे जो रॉयल्टी आती थी, वह ग्राम पंचायतों को मिलती थी। माननीय महंत जी तो हमारे बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति हैं और मैं निजी तौर पर उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हमें उनके आश्रम में भी जाने का आमंत्रण मिला है, हम जाएंगे, लेकिन पंचायतों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारविहीन किया है, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह ऐतिहासिक सत्य है, जो आज भी मौजूद है। आप गुजरात को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि गुजरात में जितने भी अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए थे, वे वापस ले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में, मेरे कार्यकाल में जिला परिषद, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे, वे सब वापस ले लिए गए हैं, लेकिन आज बुनियादी तौर पर यदि आपको ग्रामीण व्यवस्था को सुधारना है, तो ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा, उनको अधिकारसंपन्न करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि आप रेतों के खदान का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे देंगे, तो यह माफिया अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गाँव वाले उन माफिया लोगों को अपने आप काम करने से रोक लेंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहां पर खनिज के मामले में पन्ना में हीरे तक की खदान है, उसका उपयोग भी किया गया है, और भी कई ऐसी खदानें हैं, खनिज हैं। तो यह बुंदेलखंड का इलाका खनिजों से भरपूर है, वनों से भरपूर है। हम निषाद जी के संकल्प का समर्थन करते हुए यह मांग करते हैं कि उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि खड़ी फसल कटने के बाद अगर आप बुंदेलखंड जाएंगे, तो जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। आप झांसी के, ललितपुर के, महोबा के रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए, जब माइग्रेशन होता है तो प्लेटफार्म पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। गांव के गांव वहां से दूर चले जाते हैं। नरेगा की हमारी एक ऐसी योजना थी, हमारे प्रधान मंत्री जी ने उसका बहुत विरोध किया, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस बात को महसूस किया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना इस देश की आवश्यकता है। आज वे उसका श्रेय भी ले रहे हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जितना पैसा दिया जाए, उतना कम है। विशेषकर उन जिलों में, उन क्षेत्रों में, उन विकास खंडों में, उन गांवों को चिह्नित करना चाहिए, जहां से माइग्रेशन ज्यादा से ज्यादा होता है और वहां के लोगों को कम से कम सौ दिनों से सवा सौ दिनों तक रेगुलर रोजगार मिलना ही चाहिए। काम की कमी नहीं है, आजकल वहां पर क्या हो रहा है कि अधिकांश ग्राम-पंचायतों में कमीशनबाजी चली हुई है। वे लोग मजदूरों का काम करने के बजाय सीसी रोड का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का काम ज्यादा पसंद करते हैं। वहां रोजगारोन्मुखी काम की आवश्यकता को देखते हुए नरेगा का काम बढ़ाना चाहिए।

माननीय महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही

[श्री दिग्विजय सिंह]

पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस बात के लिए माननीय महंत आदित्यनाथ जी को याद दिलाएं, मैं भी इस सदन के माध्यम से महंत आदित्यनाथ जी को इस बात की याद दिलाऊंगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कर्जा माफ करने का वादा किया था। पहली कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कर्जा माफ होने की किसी चर्चा की भी शुरुआत नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जुमलेबाज़ी का एक ज़माना है और जुमलेबाज़ी में जितने हमारे उस तरफ के होशियार मित्र हैं, उतनी जुमलेबाज़ी हम लोगों ने कभी सीखी ही नहीं है। आपसे अनुरोध है कि कम से कम बुंदेलखंड के किसानों का कर्जा माफ होना आवश्यक है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं, जहाँ तक गौ-सेवा का सवाल है, हम सब गौ-सेवा के पक्ष में हैं। आपको मालूम है कि मेरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मध्य प्रदेश पहला राज्य था, जहां गौ-सेवा आयोग का गठन किया गया था और करोड़ों रुपए हमने गौ-शालाओं को दिए थे, लेकिन वहां भाजपा की सरकार आने के बाद पहले उन्होंने काम किया कि गौ-सेवा आयोग समाप्त कर दिया। ये तो गौ-सेवा के नाम पर केवल राजनीति करते आए हैं, काम तो हमने किया है, महोदय।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपके दस मिनट हो गए हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चंदेरी भी वहां का एक बहुत बड़ा कस्बा है, जहां विश्व की मानी हुई साड़ियां बनती हैं। एक ज़माना यह था कि वहां चंदेरी साड़ी उद्योग ठप होता जा रहा था, मुश्किल से बीस-पच्चीस हथकरघे रह गए थे, लेकिन तत्कालीन समय अस्सी के दशक में माधव राव सिंधिया जी यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मंत्री थे, मैं वहां पर मंत्री था, हम लोगों ने इसका नया पैकेज शुरू किया था मुझे आज आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वहां आज लगभग साढ़े तीन हजार हथकरघे चल रहे हैं और बुनियादी तौर पर जहां कोरी समाज के लोग, मुस्लिम कोरी समाज के लोग उस काम को करते थे, आज हर समाज के लोग वहां हथकरघे पर काम कर रहे हैं। इसलिए इस चंदेरी साड़ी के उद्योग पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि पर्यटन पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। खजुराहो के मंदिरों का अपना अलग महत्व है। वहाँ पर्यटन के लिए और भी ऐसे कई केन्द्र हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही अनुरोध करूँगा कि बुंदेलखंड पैकेज-। असफल रहा है। अब बुंदेलखंड पैकेज-॥ बनाते समय उन गलतियों को सुधारने के लिए और माननीय निषाद साहब ने जो प्रस्ताव दिया है, उस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए आप एक कमिटी बनाइए। आप सदन की कमिटी बना सकते हैं, सदन की कमिटी बनाइए या नीति आयोग से कहिए कि वह इसके लिए एक कमिटी बनाए, जो बुनियादी तौर पर बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों से चर्चा करने के बाद, उनकी आवश्यकता क्या है, यह जान कर पैकेज बनाए। यहाँ योजना भवन में, नीति आयोग भवन में बैठ कर जो योजनाएँ बनती हैं, उनका क्रियान्वयन पूरे तरीके से सफलता से नहीं हो पाता है। आप इसमें जनता को शामिल करिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लीजिए और

बुनियादी तौर पर जिन बिन्दुओं का मैंने उल्लेख किया है, उन बिन्दुओं के आधार पर अगर बुंदेलखंड पैकेज-II बनता है, तो हमारा इसको पूरा समर्थन होगा। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से माननीय निषाद जी के इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूँ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, निषाद जी जो संकल्प लेकर आए हैं, वह एक ऐसा संकल्प है, जिसने सदन के सभी दलों के सदस्यों को हिला कर रख दिया है। सभी ने बहुत दिल से इन विषयों का समर्थन किया है। अकेले निषाद जी ही नहीं, बल्कि रापोलू जी और बसावाराज पाटिल जी ने तो पूरी संस्कृति के क्रियाकलापों को याद करते हुए हमारे देश की जीवन प्रणाली को पुनः स्थापित करने तक का विषय रखा। डा. अनिल कुमार साहनी जी ने पहली बार माफिया वाला शब्द खुल कर सदन के सामने उजागर करने का प्रयास किया। श्री राजीव शुक्ल जी, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, हमारे आदरणीय महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया जी, सम्माननीय राज बब्बर जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आदि सभी सम्माननीय नेताओं ने कई विषयों को हमारे सामने रखा। दिग्विजय सिंह जी ने तो हमें कई चीज़ों का स्मरण भी करवाया। निषाद जी, मैं आपके इस संकल्प की बातों का विभाग के तौर पर जवाब दूँ, इसकी शुरुआत करता हूँ।

परसों गुजरात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित जी का कार्यक्रम था। वे वहाँ पधारे थे और उनके सम्मान में अहमदाबाद में रिवरफ्रंट नामक एक स्थल पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे थे और अमित जी ने वहाँ भाषण दिया। मुझे तो पता तक नहीं था कि आज यह संकल्प यहाँ आने वाला है और मुझे इसका reply करना होगा। उस भाषण में उन्होंने यह बताया कि साबरमती नदी के ऊपर जो ब्रिज था, कभी-कभी वे अपने बच्चे को स्कूटर के ऊपर बिठाकर उसके ऊपर से निकलते थे, तो उनका बच्चा उनसे पूछता था कि पापा, नदी क्या होती है? यह हमारे अध्यक्ष, अमित भाई कल माइक से बोले हैं, सभा के सामने बोले हैं। वे उसको बताते थे कि बेटा, तू कैसा सवाल करता है, जब भी हम ब्रिज cross करते हैं तो जो इसके नीचे है, वह नदी है, इसको ही नदी कहते हैं। तब वह बच्चा उनसे कहता था कि यह तो खड्डा है, नदी में तो पानी होता है। वे उसको यह समझा नहीं पाते थे कि इसको नदी कैसे कहें। कल उन्होंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि रिवर फ्रंट पर जब हम उनका सम्मान कर रहे थे और उसी के उपलक्ष्य में वहाँ सभा थी, तो उसके बगल में ही सारी साबरमती नर्मदा के जल से लबालब भरी हुई थी। निषाद जी, मैं इस बात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने नहीं, बल्कि कई सदस्यों ने इसको उजागर किया कि यह तो पंच नदियों का मुल्क है। वहां तो पांच नदियां बह रही हैं। उसी मुल्क में पानी की किल्लत की हम बात कर रहे हैं। जैसा हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य, श्री दिग्विजय सिंह जी बता रहे थे कि वे वहां के मुख्य हुआ करते थे, उस समय उन्होंने हर खेत को पानी देने का कार्यक्रम चलाया था। चलाया होगा, बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए। साबरमती नदी में पहले तो पानी था ही नहीं, मगर जैसा पानी साबरमती में आज भरा है, वैसा पानी पूरे देश की नदियों में भरा होता, यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नदी जोड़ो योजना का संकल्प लिया था, जिसे हमारे श्री शिव प्रताप शुक्ल जी ने अभी हमें याद कराया। यदि उस संकल्प को आपने अपने यूपीए-टू के समय में कार्यान्वित करने की थोड़ी सी भी कोशिश की होती, ज्यादा नहीं,

[श्री परषोत्तम रुपाला]

थोड़ी सी भी कोशिश की होती और सिर्फ बुंदेलखंड के इलाके में ही उस संकल्प के ऊपर थोड़ा सा प्रयास किया गया होता, तो आज इस इलाके की यह स्थिति नहीं होती और निषाद जी को यह संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका लेखा-जोखा करने का यह अवसर नहीं है। अब तो हमें निषाद जी के संकल्प के बारे में कहना चाहिए, क्योंकि नर्मदा जी का इतिहास हमसे ज्यादा आप जानते हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मैं और अहमद भाई, हम दोनों मिलकर पर्यावरण की मंजूरी के लिए साथ-साथ जाया करते थे, फिर भी मंजूरी नहीं मिलती थी। इस बात के हम दोनों साक्षी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेल (गुजरात): श्री राजीव गांधी जी ने उस समय इसकी परमीशन दी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री परषोत्तम रुपालाः मैं उधर बैठकर सात साल तक चिल्लाता रहा था। ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेलः श्री राजीव गांधी जी ने वर्ष 1985 में इसकी परमिशन दी थी और उस समय श्री शंकर सिंह वाघेला आपके साथ थे। उन्होंने इसका विरोध भी किया था। ...(**व्यवधान**)...

श्री परषोत्तम रुपालाः अहमद भाई, मैं सात साल तक उधर बैठे-बैठे दरवाजा लगाने की मांग करता रहा और तब दरवाजा तक नहीं लगाया गया। ...(**व्यवधान**)... मुझे जयराम जी बता रहे थे कि जब आप इधर बैठा करते थे, तो आप यहां से बहुत बोला करते थे। ...(**व्यवधान**)... मगर मैं यही बोला करता था कि हमें इस बांध की परमीशन दी जाए, लेकिन नहीं दी जाती थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेलः बांध की परमिशन डा. मनमोहन सिंह जी ने दी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री परषोत्तम रुपालाः नहीं दी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेलः बिल्कुल दी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री परषोत्तम रुपालाः नहीं दी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेलः श्री जेटली जी और मैं साथ-साथ गए थे। तब डा. मनमोहन सिंह जी ने permission दी थी और उस दिन sunday था। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दिनांक 13 अप्रैल, 1987 को नर्मदा प्रोजेक्ट को clearance मिली थी। उस समय डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय इसकी अनुमति मिली थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेलः उस समय आपने चूंकि इसकी केनाल नहीं बनाई थी, इसलिए पानी नहीं मिला था।

श्री परषोत्तम रुपालाः यही तो मैं बता रहा हूं। कल उस पानी को देख कर ही तो उन्हें बोलना पड़ा। आपके कार्यकाल में वहां पानी नहीं आया था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जुमलेबाजी के नारे लगाने बन्द करिए। इन नारों को लगाते-लगाते देश की जनता थक गई। ...(**व्यवधान**)... आप हमें इस चुनाव के नारे की याद दिला रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया, देश के 80 करोड़ गरीब आज पूछ रहे हैं? गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ कहते-कहते वे थक गए, लेकिन आप गरीबी नहीं हटा सके। इसलिए उन्होंने आपको हटा दिया। ...(**व्यवधान**)... तभी जाकर यह ठीक हुआ। तब जाकर आज कुछ काम हुआ। ...(**व्यवधान**)... आज हमारा इस बात से कोई झगड़ा नहीं है। जो भी अच्छे काम किए, आपने ही किए, यह कहने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, राजीव शुक्ल जी ने गांधी जी का स्मरण किया। हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी और भावुक बात आपने कही। महात्मा गांधी जी के जीवनकाल की एक बहुत ही संवेदनशील बात आपने इस गृह माध्यम से, गृह के सदस्यों के सामने और देशवासियों के सामने रखी। जब महात्मा गांधी जी ने यह संकल्प लिया होगा। जब देश की जनता से इसकी अपील की जाती थी, तब कोई कारण रहा होगा कि देश की जनता ने महात्मा गांधी जी के इस यज्ञ में सहयोग देने का प्रण और व्रत लिया होगा। जब ऐसे संकल्प हमारे सामने आते हैं, तब राष्ट्र में बड़े परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। जैसा आपने उल्लेख किया कि इस समय वहां Tourism पर बल देने की आवश्यकता है। आपने इस एरिया के अनेक नाम गिनाए, माननीय सदस्यों ने भी बताए, उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम तुलसीदास का सामने आता है। मैं समझता हूं कि तुलसीदास जी से बड़ा कोई नाम इस कालखंड में हमें दूसरा नहीं मिल सकता है। उन्होंने रामचरित मानस ग्रंथ की रचना की थी। वह उनकी कर्मभूमि रही है। इस ग्रंथ को उन्होंने वहीं लिखा। उस समय पांडुलिपि में लिखा ग्रंथ आज भी वहां मौजूद है, ऐसा एक माननीय सदस्य ने बताया, मगर उस स्थान की प्रसिद्धि न होने के कारण लोग वहां जाने और दर्शन करने के लिए प्रेरित नहीं होते। इसके अलावा, दूसरे कई तीर्थ उस क्षेत्र में हैं। चित्रकूट से लेकर जिन-जिन तीर्थस्थलों की चर्चा यहां की गई, उन सभी स्थलों को जोड़कर, यदि टूरिज्म सर्किट के रूप में विकास किया जाए, तो वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों को आय के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

निषाद जी भी सुन रहे होंगे, जब उनके संकल्प पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। केन्द्र में चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, यू.पी.ए. की हो या किसी भी दल की हो, जो पैसा यहां से sanction करके वहां भेजा जाता था, बब्बर जी और शायद दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सही बात कही कि हमने वहां लगभग 8,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम का पैकेज दिया, किसी छोटे प्रदेश के लिए यह मामूली रकम नहीं होती, मगर उसका कोई फलसफा उन्हें नहीं मिला। धरती पर उसे उतारने की कोशिश नहीं हुई। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि जिन लोगों के लिए वह पैकेज़ भेजा गया था, उनके पास जाने की बजाए, उस पैसे से कुछ माफियाओं ने अपने घर भर लिए। जब आप ऐसी बातें सुन रहे थे तो आपको कुछ नहीं हो रहा था? आपने जिक्र किया कि वहां कुछ पानी के टैंकर आते थे, लेकिन गरीबों के घरों के स्थान पर वे कुछ असरदार लोगों के घर चले जाते थे। मैं समझता हूं कि इस सृष्टि का ऐसा रिवाज़ है कि जब कानून का राज खत्म हो जाता है, तो फिर दबंगों का राज ही चलता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए राज्य सरकारों को थोड़ा

[श्री परषोत्तम रुपाला]

सावधानी से, सतर्कता से और ताकत से काम लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ। शायद, अभी काम शुरू हुआ है, ऐसा अखबारों की सुर्खियों से पता चलता है। योगी जी के नाम से ही कुछ कारोबार वहां बंद हो गए हैं। मेरी कामना है कि आगे चलकर उनका और ज्यादा असर इस इलाके में भी दिखाई दे। खास तौर से आपके इलाके में माफियाओं से संबंधित जो मुद्दा है, उसके साथ वहां की सरकार सख्ती से पेश आएगी और उस व्यवस्था को समाप्त करके राज्य के साथ राष्ट्र का भी कल्याण करेगी। गरीबों के लिए जो भी रकम तिजोरी से जाती है, उसे सही जगह पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। मित्रों, मुझे निषाद जी को बताना था ...(**व्यवधान**)... मित्रों की बीमारी तो नहीं है, मगर आप याद कराते रहेंगे तो हम बोलते रहेंगे। ...(**व्यवधान**)...

हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसी साल वहां के मुख्य मंत्री जी के साथ बैठक करके कृषि सिंचाई योजना के तहत 49 करोड़ रुपए का आबंटन माघ महीने में किया था। उस राशि में से 29 करोड़ रुपया यहां से विमुक्त भी कर दिया गया। मगर फरवरी तक उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इसीलिए शेष राशि अभी तक यहां से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। आप सब मित्रों के साथ-साथ निषाद जी ने भी किसानों की स्थिति का वर्णन किया। मैं खुद भी किसान हूं। मैं खुद भी एक किसान हूँ। किसानों की स्थिति का जब भी कोई जिक्र करता है, तो हम बड़े ग़ौर से उसकी और देखते हैं और उसे सुनते भी हैं। सभी का एक ही कहना होता है कि उसके खेत में पानी पहुँचे, उसको खेती की टेक्नोलॉजी मिले। आपने खाद, बीज का जिक्र किया और पानी का भी जिक्र किया। यह जिक्र बहुत सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह जिक्र आज ही हुआ है, बल्कि यह वर्षों से चल रहा है। मैं जब बच्चा था और सभाओं में लोगों की बातें सुनने के लिए जाता था, तो मैं उन्हीं सभाओं में सुनता था कि यह देश किसानों का देश है, यह देश गाँवों का देश है, यह देश कृषि-प्रधान देश है, जब कृषि ठीक होगी, तो ही देश ठीक होगा। मैं ये बातें सुनते-सुनते कृषि मंत्री बन गया और आज भी मुझे यही सुनने को मिल रहा है, हम यही सुन रहे हैं।

दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि पंचायतों को जो अधिकार उन्होंने दिए थे, उनको भी हमारी सरकार ने आने के बाद समाप्त कर दिया। मुझे आपको स्मरण कराना है कि आपके ही एक सम्माननीय प्रधान मंत्री जी, श्रीमान् राजीव जी ने यह बात publicly कही थी कि हम यहाँ से एक रुपया भेजते हैं, तो गाँव तक पहुँचते-पहुँचते वह 15 पैसा हो जाता है। यह निवेदन सिर्फ श्रीमान् राजीव जी का नहीं था, बल्कि देश के एक प्रधान मंत्री का था। उसके बाद भी बहुत लम्बे अर्से तक आपका शासन रहा, तब आपने इस सवाल का क्या जवाब निकाला? यह एक प्रधान मंत्री की पीड़ा थी। आज तो हम एक सामान्य आदमी की पीड़ा की चर्चा कर रहे हैं, जबकि वे तो खुद एक प्रधान मंत्री थे और उन्होंने यह कहा था। मैं अपने प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूँढ़ लिया। पहले जो एक रुपया गाँव तक पहुँचते-पहुँचते 15 पैसा हो जाता था, आज भारत सरकार की तिजोरी से निकला हुआ रुपया शत-प्रतिशत पंचायत के एकाउंट में पहुँचता है। सवाल आपका था, जवाब हमारे प्रधान मंत्री जी ने ढूँढ़कर दिया है। आपकी पार्टी की ओर से इनको कम से कम इसके लिए तो धन्यवाद जाना चाहिए, यह मेरा आपसे नम्र अनुरोध है। ...(**व्यवधान**)... यह एक बात तो आपको

कहनी चाहिए, यह आपका सवाल था। आज वह सीधे जा रहा है और हम 489 रुपये per head, per year हर ग्राम पंचायत को यहाँ से दे रहे हैं। वह यहाँ से सीधे उनके एकाउंट में जाता है। एक संघीय ढाँचा होने के चलते वह पैसा via State body ही जाता है, लेकिन यदि राज्य की सरकार पंचायत को वह पैसा 15 दिन में नहीं पहुँचा पाती है, तो राज्य सरकार को आरबीआई के रेट से पंचायत को ब्याज देना पड़ता है। हमने उस योजना में यह प्रावधान किया है। इसीलिए राज्य की सरकारें भी इसको तुरंत उनके पास पहुँचा रही हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते थे, इसको आप भी कर सकते थे और आपको यह करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब यह हो गया।

आपने पंचायत में अधिकार की बात कही। आपने मुख्य मंत्री के काल-खंड में यह किया होगा, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। PESA Act का जो बिल था, उसके रूल्स नहीं बने थे, उसको करीब दो महीने पहले गुजरात सरकार ने बना दिया। उसी के चलते, खासकर एसटी ब्लॉक में हर ग्राम पंचायत को खनिज और वन-सम्पदा के पूरे अधिकार वहाँ दे दिए गए। वहाँ एसटी बेल्ट की पूर्व पट्टी के जितने भी जिले हैं, उनके लिए यह किया गया। ये बिन्दु आपकी ओर से और सम्माननीय सदस्यों की ओर से आए हैं। किसी ने एक बिन्दु, खासकर नीलगाय के संबंध में भी उपस्थित किया गया था। रापोलू जी ने भी उठाया था और साहनी जी ने भी उठाया था, हम गुजरात में इन्हें "रोजड़ा" कहते हैं। इसलिए "रोज" बोलने में आगे की कार्यवाही करने में कोई आपदा नहीं होती है। इसमें मेरा अनुरोध है कि जिन राज्य सरकारों ने, खासकर बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से permission मांगी, उसी तर्ज पर जो भी राज्य सरकारें इसके लिए permission मांगेंगी, उन्हें भारत सरकार की ओर से permission दी जाएगी। यह बात सही है कि जो नील रोज है, वह किसान के पूरे तैयार पाक को बरबाद कर देती है और उससे इतनी भारी परेशानी होती है कि अगर एक घंटा भी चूक गए - आप 24 घंटे उसकी रखवाली करते हैं, लेकिन अगर उसमें से 1 घंटे के लिए भी कहीं आगे-पीछे चले गए या सो गए तो उस एक घंटे में ही वे आपके पूरे खेत को खत्म कर देते हैं। इस सबके चलते इनके संबंध में कार्यवाही करने की जो आवश्यकता है, वह कुछ प्रान्तों में हो गयी है। उसी तर्ज पर जो प्रांत केन्द्र सरकार से permission मांगेंगे, केन्द्र सरकार उन्हें वह permission जरूर देगी।

सर, जो बुंदेलखंड का प्रस्ताव है, मुझे लगता है कि दो प्रदेशों के बीच उसका बंटवारा है - इसमें मध्य प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों इलाकों की समस्याओं में भी थोड़ा अंतर है। आज कृषि के लिए दिग्विजय सिंह जी के मध्य प्रदेश ने बीस प्रतिशत तक की कृषि की विकास दर हासिल की है - बीस प्रतिशत की।

श्री दिग्विजय सिंहः फ्रॉड है।

श्री परषोत्तम रुपालाः फ्रॉड है।

श्री दिग्विजय सिंहः विश्व के इतिहास में एक राज्य, एक इलाका बता दीजिए जहाँ पांच परसेंट से ज्यादा agriculture की growth कहीं हुई हो।

श्री परषोत्तम रुपालाः एक मिनट सर, आप बाद में बोल दीजिएगा, अगर आपको कुछ कहना है

[श्री परषोत्तम रुपाला]

तो आप बाद में अपनी बात कहिएगा - जो मैंने बीस प्रतिशत कहा, आप इसको मानें न मानें, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और वहां की जनता को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ग्रोथ रेट, आंकड़े, agricultural produce और अन्य जो चीज़ें हैं, उनके जरूर कहीं न कहीं आगे पीछे बातें आ सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना जहां किसानों को ज़ीरो परसेंट रेट पर ऋण मिल रहा है, इसमें कौन इन्कार करेगा? ज़ीरो परसेंट रेट...

श्री भुपेन्द्र यादव (राजस्थान): सब्सिडी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री परषोत्तम रुपाला: ज़ीरो परसेंट रेट नहीं, बल्कि माइनस दस परसेंट पर मिल रहा है। ...(**व्यवधान**)... यह है। दिग्विजय जी, ऐसी बातों का विरोध मत करिए। आपको मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आपको फिर से दिक्कत होगी।

श्री दिग्विजय सिंह: यह जुमलेबाजी गुजरात से शुरू हुई है और पूरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में चल रही है। यह टोटल जुमलेबाजी है। वहां किसी भी किसान को ज़ीरो परसेंट interest पर कर्ज़ा नहीं मिल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी और संघ के ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेल: आप गुजरात में शरू करा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: आप मध्य प्रदेश किसान संघ के अध्यक्ष शर्मा जी से पूछ लीजिए, अगर किसी भी किसान को ज़ीरो प्रतिशत पर लोन मिला हो तो। ...(**व्यवधान**)...

श्री परषोत्तम रुपाला: एक नहीं, यदि आप चाहें तो मैं एक हज़ार किसानों की लिस्ट यहां रख दूं, जिन्हें ज़ीरो परसेंट पर लोन मिला है - ऐसे हज़ारों किसानों की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री अहमद पटेल: गुजरात में शुरू करा दीजिए, अच्छी बात है।

श्री परषोत्तम रुपाला: अहमद भाई, आप अलग बात मत करिए। ...(**व्यवधान**)... गुजरात में अगर अहमद भाई की शुभकामनाएं होंगी ...(**व्यवधान**)... गुजरात में शुरू करने की उनकी डिमांड के साथ भी मैं सहमत हूं और राजकोट में यह शुरू हो भी गया है। राजकोट डिस्ट्रिक्ट में ज़ीरो परसेंट पर शुरू हो भी गया है, वह आगे भी बढ़ेगा। यह हुआ है, उसे आप कहां मना कर पाएंगे? यह तो होगा ही होगा ...(**व्यवधान**)... लम्बा हो रहा है? मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा। भाई, यह चुनावी भाषण नहीं है। अभी मुझे बुंदेलखंड के बारे में ही बताना था। ...(**व्यवधान**)... भारत में किसानों की समस्याओं का निदान करने हेतु पहली बार इस देश को ऐसा प्रधान मंत्री मिला ...(**व्यवधान**)...

कुछ माननीय सदस्य: आप बुंदेलखंड पर बोलिए।

श्री परषोत्तम रुपाला: बुंदेलखंड के किसानों की आय दोगुनी हो, इसकी घोषणा की। यह चुनाव की घोषणा नहीं थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः जुमले वाली बात।

श्री परषोत्तम रुपालाः हां, उसको बंद करने की जनता मोहर लगा रही है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा और मुझे एक हिदायत भी देनी है कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना जो लायी गई है, यह सिर्फ किसानों को निश्चित रूप से उनकी खेती के लिए पानी मिले, इसीलिए इस योजना की घोषणा की गई। उसमें 20,000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई और इसमें 99 योजनाओं को चिन्हित किया गया। वे 99 योजनाएं कौन सी थीं? वे जो दस साल, पन्द्रह साल पुरानी थीं, जो कभी आपके ही कार्यकाल में बनी होंगी, आपने ही सपने संजोये होंगे, उनको शुरू किया होगा, आपने सोचा होगा कि ये योजनाएं ही होंगी, जो किसानों के लिए लाभकारी होंगी। किसी कारणवश वे पूरी नहीं हो पा रही थीं, तो उन्हें 99 योजनाओं को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उनमें से चार योजनाएं ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः आपने Accelerated Irrigation Benefits Programme को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम दिया। आपने बस उतना ही किया है। ...(**व्यवधान**)... आपने AIBP को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम दिया है।

श्री परषोत्तम रुपालाः क्या यह 20,000 करोड़ रुपया भी उसी नाम के साथ आया है? उसी में से 20 योजनाएं अभी इसी महीने में पूरी हो गयीं और उसी में से चार योजनाएं बुंदेलखंड की भी हैं। उसी को मंजूर किया है, उसी को पानी मिले, इसलिए किया है। उसी का नाम चाहे जो दे सकता हूं। ...(**व्यवधान**)... उन चार योजनाओं में से तीन बुंदेलखंड के एरिया में है और योजना उत्तर प्रदेश के एरिया में है।

मुझे आपको बताते हुए यह भी खुशी है और जिसका जिक्र कई सदस्यों ने किया है, जो कि Ken-Betwa River-Linking Project है। आप बताइए साहब, वह 2002 में शुरू हुई और अब हम 2017 में चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2002 में उसकी शुरुआत हुई और इसको clearance मिलने में इतना समय लग गया। इनको principle clearance जो wildlife का लेना था, वह 10.05.2016 को मिला। यह 2002 की योजना है। आप बताइए कि इसमें क्या किया? ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः आपकी मध्य प्रदेश सरकार सोती रही।

श्री परषोत्तम रुपालाः अब यह clearance मिल गयी है और आगे की भी clearance हम देंगे। इस योजना को पूरी करके हम बुंदेलखंड के किसानों के लिए काम करेंगे। बुंदेलखंड की इन योजनाओं को सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि वहां के किसानों को अच्छे बीज मिलें, अच्छी टेक्नोलॉजी की जानकारी मिले, इसके लिए भी हमारे विभाग की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। यहां के पशुधन को संरक्षण देने के लिए और उसमें बढ़ोत्तरी हो, वहां पर दुग्ध की प्रवृत्ति बढ़े, इसके लिए भी इस सरकार ने पहली बार आठ हजार करोड़ रुपया डेयरी सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए दिया है। इसका भी बेनिफिट उसी इलाके के लोगों को मिलेगा।

सबसे पहले जो drip irrigation है, जिसको हम micro water management कहते हैं, यह पांच

[श्री परषोत्तम रुपाला]

नदियों का प्रदेश होते हुए भी सूख गया। किसान flow irrigation से खेती करते हैं, इसकी एक वजह यह भी है। इसी को drip में convert करने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी राशि का प्रबंधन किया है। हम इसे भी आप के क्षेत्र में लागू करने के प्रयास कार्यान्वित करवाएंगे। इस तरह केन्द्र सरकार की नीयत, नरेन्द्र भाई मोदी का मार्गदर्शन और अब वहां योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति, निश्चित रूप से बुंदेलखंड के किसानों को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए एक निश्चित समय की मर्यादा में काम करने का प्रयास शुरू होने की संभावनाएं पूरी-पूरी बन गयी हैं। इसीलिए मैं बहुत ही विनम्रता से माननीय निषाद जी से उनका संकल्प वापस लेने की विनती करता हूं।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मैं सब से पहले तो आभारी हूं कि मुझे भी इस चर्चा में बोलने का अवसर मिला। महोदय, हमारे सम्माननीय मंत्री जी ने सारे बिंदुओं पर अपनी बात रखी है।

अभी दिग्विजय जी ने कहा कि बुंदेलखंड पैकेज का अध्ययन होना चाहिए। महोदय, बुंदेलखंड पैकेज वर्ष 2009 में शुरु हुआ था और 2012-13 में "निष्कर्ष मूल्यांकन अध्ययन" नाबार्ड परामर्शदात्री सेवा द्वारा किया गया था। इस के अध्ययन से पता चला कि सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अर्जित उपलब्धियां 21 प्रतिशत हैं और मध्य प्रदेश में 88 प्रतिशत हैं। वर्ष 2012-13 में मोदी सरकार नहीं थी और मध्य प्रदेश में आप की सरकार नहीं थी। आप मुख्य मंत्री नहीं थे। उस अध्ययन की रिपोर्ट थी कि उत्तर प्रदेश में इस पैकेज के कारण सिंचाई के क्षेत्र में 21 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 88 प्रतिशत उपलब्धियां थीं। इन में वर्षा ऋतु में लगायी फसलों की उपज में 83 प्रतिशत और शीतकालीन फसलों की उपज में 42 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। उस अवधि के दौरान वर्ष 2009-10 की तुलना में 2012-13 में वृद्धिकृत फसल के कारण किसानों की आय में 34 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ। यह आपकी सरकार के समय की रिपोर्ट है और रिपोर्ट चाहे आप की सरकार हो या हमारी सरकार हो, देश की कृषि विकास दर, राज्य की कृषि विकास दर या इस प्रकार के अध्ययन के आंकड़े पहले से चले आते हैं। तो यदि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 20 प्रतिशत एक fraud है, तो शायद आजादी के बाद से आपने जितने आंकड़े प्रस्तुत किए होंगे, वे सारे fraud ही थे, लेकिन मैं इस से सहमत नहीं हूं। यह प्रामाणिक तरीके से चली आ रही प्रक्रिया है। ...(**व्यवधान**)... नहीं, आपने कहा कि यह fraud है, जब मध्य प्रदेश की चर्चा आयी, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं और सदन भी सहमत नहीं होगा क्योंकि पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था है, जिस के आधार पर हम आज भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं। इन 70 वर्षों में से 60 वर्ष, इन आंकड़ों को लाने की अगुवाई आपने की है।

श्री दिग्विजय सिंहः आप किसी अन्य राज्य का पता लगा लीजिए, बता दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं अभी यही कह रहा हूं कि आंकड़े इकट्ठे करने की व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आपकी प्रोसेस थी, वही प्रोसेस है। तो एक तो यह अध्ययन वाली बात हुई। दूसरी बात, हमारी साथी मंत्री बता रहे थे कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह आपका ही दिया नाम था। मैं इसे मानता हूं, लेकिन इसी सदन में लोक सभा में और राज्य सभा में भी, हम जब से कृषि मंत्री बने हैं, तब से आपकी ओर से और चारों ओर से यह सुनते आए हैं कि देश के अंदर मध्यम

5.00 P.M.

एवं बड़ी 99 परियोजनाएं, हमारे मंत्री जी ने 10 वर्ष कहा है, लेकिन आप रिकॉर्ड देख लें कि ये 25-25 वर्षों से लंबित थीं और इन 99 परियोजनाओं के लिए 80 हजार करोड़ रुपए चाहिए थे, जिस से 76 लाख हैक्टेयर की सिंचाई हो सकती थी। ये सारे रिकॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन हम पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए और ये योजनाएं अधूरी रह गयीं। इसलिए इतना तो मानना ही पड़ेगा कि नाम भले आप का हो, हमने नाम बदला, लेकिन व्यवस्था लगायी कि इन परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जाए। मैं मानता हूं कि किसी ने बच्चा पैदा किया, यह उस का बड़प्पन है, लेकिन उसका लालन-पालन करना, उसे बड़ा बनाना, उसे शिक्षित बनाना और उसे ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाना, यह बहुत बड़ा दायित्व होता है। अब 99 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 20 हजार करोड़ का corpus fund बनाया गया।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मंत्री जी, समय पूरा हो गया है, पांच बज गए हैं, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं।

SPECIAL MENTIONS*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Shri Vijayasai Reddy; please lay it on the Table.

Demand to take strict measures for implementation of The Prohibition Of Child Marriage Act, 2006 in the country particularly in Andhra Pradesh

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I wish to bring to the notice of the House the continued prevalence of child marriages in India, particularly in Andhra Pradesh. Despite the enactment of the Prohibition of Child Marriage Act in 2006, the practice has continued unabated for more than a decade.

According to the National Commission for Protection of Child Rights, 1.71 lakh girls and 1.73 lakh boys were married off in the last five years in Andhra Pradesh before they reached the marriageable age. Krishna district tops the Statewide list of child marriages, with 20,584 girls and 19,557 boys (2.4% of boys) getting married before attaining 18 and 21 years of age. Visakhapatnam district came second, with marriage of 16,876 girls below 18 years of age, followed by Anantapuram (16,738), Kurnool (16,532) and Chittoor (15,769). These shocking trends are also being witnessed across India. In 2013, 43 per cent women aged between 20 and 24 years were married before 18. Moreover, the UNICEF suggests that there are 23 million child brides in India. This makes for, approximately, 40 per cent of child brides globally.

*Laid on the Table.